सांध्य दैनिक

श्रीकंचनपथ

RNI. Reg. No. CHHHIN/2009/30534
डाक पंजीयन क्रं.-छ.ग./दुर्ग/1000000029/2026-28

लीपा पोती नहीं सिर्फ सच

वर्ष- 17 अंक - 318 | www.shreekanchanpath.com | संस्थापक एवं प्रेरणास्रोत- स्व. श्रीमती रजनी अग्रवाल | भिलाई, मंगलवार 01 सितंबर 2026 | पृष्ठ 8- मूल्य 1/-

खास-खबर

भिलाई, रिसाली और भिलाई-चरोदा निगम के वार्डों का आरक्षण 9 सितंबर को

भिलाई। जिले के नगरीय निकायों में निष्पक्ष एवं पारदर्शितापूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया सुनिश्चित करने की दिशा में प्रशासनिक स्तर पर गतिविधियां जारी है। इसी क्रम में कलेक्टर अभिजित सिंह ने छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के तहत जिले के तीन प्रमुख नगर पालिक निगमों- भिलाई, रिसाली और भिलाई-चरोदा के वार्डों का आरक्षण तय करने हेतु औपचारिक आदेश जारी कर दिया है। जारी समय-सारणी के अनुसार, तीनों नगर निगमों का वार्डवार आरक्षण कार्यक्रम 09 सितंबर 2026 को सेक्टर-6, भिलाई स्थित कला मंदिर (सिविक सेंटर) में आयोजित किया जाएगा। तय कार्यक्रम के तहत पूर्वाह्न 11.00 बजे से नगर पालिक निगम भिलाई, अपराह्न 03.00 बजे से नगर पालिक निगम रिसाली तथा सायंकाल 05.00 बजे से नगर पालिक निगम भिलाई-चरोदा के वार्डों के आरक्षण की कार्यवाही संपन्न की जाएगी।

एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसाः ट्रक में घुसी तेज रफ्तार पिकअप, छह लोगों की मौत

पलवल। हरियाणा के पलवल जिले में कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) एक्सप्रेसवे पर मंगलवार सुबह करीब 5:30 बजे भीषण सड़क हादसा हो गया। इसी दौरान अनियंत्रित हुई पिकअप सड़क किनारे खड़े ट्रक से पीछे से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार लोगों में चीख-पुकार मच गई। हादसे के बाद आसपास से गुजर रहे राहगीर मौके पर पहुंचे। उन्होंने पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी। पुलिस और स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद पिकअप में फंसे लोगों को बाहर निकाला। सभी घायलों को उपचार के लिए जिला नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने छह लोगों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान विजय सिंह, राजकुमार, रेशमा देवी, कमला देवी, सुधा और महेश के रूप में हुई है।

इंडिगो की फ्लाइट का इंजन फेल, गोवा में इमरजेंसी लैंडिंग

पणजी। इंडिगो की गोवा-दिल्ली फ्लाइट को मंगलवार गोवा में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। उड़ान के दौरान इंजन में खराबी की सूचना मिलने पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ञ्झष्ट) ने कुछ समय के लिए फुल इमरजेंसी घोषित कर दी थी। यह जानकारी सूत्रों के मुताबिक है। इंडिगो की फ्लाइट 6E 2102 सुबह 9:16 बजे गोवा से रवाना हुई, लेकिन एक इंजन में खराबी की सूचना मिलने के बाद वह एयरपोर्ट वापस लौटने लगी। सूत्रों के मुताबिक, सुबह करीब 9:30 बजे, ञ्झष्ट ने फुल इमरजेंसी घोषित कर दी, क्योंकि सुरक्षित लैंडिंग के लिए विमान को वापस गोवा की ओर मोड़ा जा रहा था। हवाई जहाज सुबह 9:51 बजे रनवे 28 पर सुरक्षित उतरा और स्टैंड 6 पर पूरी तरह से पार्क हो गया, जिसके बाद एटीएस ने सुबह 10:03 बजे फुल इमरजेंसी खत्म कर दी। सभी यात्री सुरक्षित रूप से उतरे और उन्हें बोर्डिंग एरिया में ठहराया गया।

हिड़मा जैसे कुख्यात नक्सली को आदर्श मानने वाले ही दिमागी नक्सली - मुख्यमंत्री साय

मुख्यमंत्री ने कहा - बस्तर अब भय और हिंसा से निकलकर शांति, विश्वास और विकास की नई राह पर

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नक्सलवाद के समर्थन में बात करने वाले और कुख्यात नक्सली हिड़मा, जिसने सैकड़ो निर्दोषों की हत्या की, उसे आदर्श मानने वाले ही दिमागी नक्सली हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ नक्सलवाद के लंबे और पीड़ादायक दौर से बाहर निकलकर शांति, विश्वास और विकास की नई राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारे सुरक्षाबलों के अदम्य साहस, केंद्र और राज्य सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति तथा बस्तर के लोगों के सहयोग से नक्सलवाद समाप्ति की ओर है। अब आवश्यकता इस बात की भी है कि हिंसा और नक्सलवाद को वैचारिक समर्थन देने तथा उसका महिमामंडन करने वाली मानसिकता को समाज स्पष्ट रूप से अस्वीकार करे।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भी कुछ लोग ऐसे कुख्यात नक्सलियों को अपना आदर्श मानते हैं, जिनके हाथ निर्दोष नागरिकों और सुरक्षाबलों के खून से रंगे रहे हैं। हिड़मा जैसे नक्सलियों ने हिंसा और आतंक के माध्यम से बस्तर की अनेक पीढ़ियों को भय, अभाव और पिछड़ेपन में रखने का काम किया। ऐसे लोगों का महिमामंडन करना, उनके समर्थन में नारे लगाना या उन्हें नायक के रूप में प्रस्तुत करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं ठहराया जा सकता।

बंदूक उठाने वाला समाज का आदर्श नहीं हो सकता

मुख्यमंत्री ने कहा कि बंदूक उठाकर निर्दोष लोगों की जान लेने वाला व्यक्ति किसी समाज का आदर्श नहीं हो सकता। नक्सली हिंसा में बस्तर ने अपने हजारों निर्दोष नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और बहादुर जवानों को खोया है। अनेक परिवारों ने अपनों को खोने का दर्द सहा, बच्चों से उनके माता-पिता छिने और विकास की संभावनाओं को दशकों तक बाधित किया गया। हिंसा के जिम्मेदार लोगों का गुणगान करना बस्तर के पीड़ित परिवारों और शहीद जवानों के बलिदान का भी अपमान है।

नक्सलवाद बंदूक और जंगलों तक सीमित चुनौती नहीं

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि नक्सलवाद केवल बंदूक और जंगलों तक सीमित चुनौती नहीं है। हिंसा को उचित ठहराने, लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति अविश्वास पैदा करने और नक्सली हिंसा के जिम्मेदार लोगों को नायक के रूप में स्थापित करने वाली सोच भी उतनी ही चिंताजनक है। लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात रखने और असहमति व्यक्त करने का अधिकार है, लेकिन हिंसा का समर्थन और निर्दोष लोगों की हत्या करने वालों का महिमामंडन किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि आज बस्तर की पहचान बदल रही है। जिस क्षेत्र को कभी नक्सली हिंसा, बारूदी सुरंगों और भय के कारण जाना जाता था, वहां अब स्कूलों की घंटियां सुनाई दे रही हैं, सड़कें बन रही हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच रही हैं, युवाओं को शिक्षा और रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं तथा दूरस्थ गांव शासन की योजनाओं और विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं।

युवा अब बंदूक नहीं, कौशल और रोजगार चाहते हैं

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बस्तर के युवा अब बंदूक नहीं, किताब, कलम, कौशल और रोजगार चाहते हैं। वे अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं और देश-प्रदेश की प्रगति में भागीदार बनना चाहते हैं। हमारी सरकार का संकल्प है कि बस्तर के प्रत्येक युवा को आगे बढ़ने का अवसर मिले और प्रत्येक परिवार तक विकास तथा सुशासन का लाभ पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सलवाद के विरुद्ध लड़ाई केवल सुरक्षा की लड़ाई नहीं थी, बल्कि बस्तर के भविष्य को बचाने की लड़ाई थी। हमारे जवानों ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना इस लड़ाई को निर्णायक मुकाम तक पहुंचाया है। अब समाज की जिम्मेदारी है कि हिंसा की विचारधारा को किसी भी स्वरूप में महिमामंडित न होने दे।

हिंसा के लिए छत्तीसगढ़ में कोई स्थान नहीं

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ शांति, लोकतंत्र और विकास के मार्ग पर आगे बढ़ चुका है। नक्सलवाद और हिंसा के लिए नए छत्तीसगढ़ में कोई स्थान नहीं है। बस्तर की नई पीढ़ी के आदर्श वे लोग होने चाहिए जो शिक्षा, सेवा, परिश्रम, नवाचार और राष्ट्र निर्माण के माध्यम से समाज को आगे बढ़ा रहे हैं, न कि वे जिन्होंने बंदूक और हिंसा के सहारे निर्दोष लोगों का जीवन छीना। उन्होंने कहा कि बस्तर में शांति की स्थापना केवल सरकार या सुरक्षाबलों की उपलब्धि नहीं, बल्कि वहां के नागरिकों के साहस और विश्वास की जीत है। अब इस शांति को स्थायी बनाते हुए बस्तर को विकास, पर्यटन, शिक्षा, रोजगार और समृद्धि की नई पहचान देना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

तोखन साहू बन सकते हैं बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष

रायपुर। छत्तीसगढ़ बीजेपी में आगामी दिनों में नया बदलाव देखने को मिल सकता है। राजनीतिक हलचलों के बीच केंद्रीय राज्य मंत्री और बिलासपुर सांसद तोखन साहू को दिल्ली बुलाया गया है। विधानसभा चुनाव से ठीक ढाई साल पहले सियासी गलियारे में इस बात की चर्चा है कि साहू को छत्तीसगढ़ बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। क्योंकि वर्तमान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव सड़क हादसे में घायल हैं और वे स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। ऐसे में ये कयास लगाये जा रहे हैं कि साहू को छत्तीसगढ़ बीजेपी की कमान सौंपी जा सकता है।

इस बात की पुष्टि इस बात से भी होती है कि पिछले दिनों तोखन साहू ने प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनके नाम की चल रही चर्चाओं के बीच बड़ा बयान देते हुए कहा कि वे बीजेपी के एक छोटे से कार्यकर्ता हैं। पार्टी जो आदेश देती है उसे निभाते हैं। पार्टी ने मुझे जब-जब जो जिम्मेदारी दी, उसे मैंने पूरी तरह से निभाया है। पार्टी का हर फैसला मुझे स्वीकार है। मौजूदा वक्त में जो भी निर्णय पार्टी की ओर से लिया जाएगा, उसे मैं सहर्ष स्वीकार करुंगा और पूरी ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभाऊंगा।

केआर महापात्रा बन सकते हैं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की सिफारिश

श्रीकंचनपथ न्यूज

बिलासपुर। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के अगले चीफ जस्टिस के रूप में ओडिशा हाईकोर्ट के जज न्यायमूर्ति केआर मोहपात्रा के नाम की सिफारिश की है। 6 अगस्त 2026 को हुई सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक में यह निर्णय लिया गया। यह सिफारिश वर्तमान मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा के 4 सितंबर 2026 को सेवानिवृत्त होने के बाद की जाने वाली नियुक्ति के संबंध में है।

वर्तमान मुख्य न्यायाधीश आगामी 4 सितंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। इसके बाद जस्टिस केआर मोहपात्रा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। हालांकि, नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही उनकी औपचारिक नियुक्ति होगी।

कौन हैं जस्टिस केआर मोहपात्रा?

जस्टिस मोहपात्रा का जन्म 18 अप्रैल 1965 को हुआ था। उन्होंने बीए और एलएलबी की शिक्षा प्राप्त की है। वे दिवंगत न्यायमूर्ति शरत चंद्र मोहपात्रा के पुत्र हैं। उन्होंने 7 फरवरी 1988 को ओडिशा स्टेट बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में नामांकन कराया था। उन्होंने सिविल, सर्विस, क्रिमिनल और संवैधानिक कानून समेत कानून की विभिन्न शाखाओं में करीब 26 वर्षों तक वकालत की।

पूर्व सीएम बघेल के पीए रहे केके के घर में ईडी का छापा

■ दो गाड़ियों से पहुंची टीम, दस्तावेजों की हो रही जांच-पड़ताल

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के पीए रहे केके चंद्रवंशी के घर पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की रेड पड़ी है। मंगलवार की सुबह छह बजे के आस-पास ईडी की टीम ने छापा मारा है। दो गाड़ियों में सवार होकर पांच से आठ अधिकारियों की टीम पहुंची हुई है। फिलहाल दस्तावेजों की जांच पड़ताल की जा रही है।

बताया जाता है कि ईडी के करीब आठ अधिकारी सुबह छह बजे के आस-पास दो गाड़ियों में सवार होकर चंद्रवंशी के पुरानी भिलाई के निवास पर पहुंचे। टीम घर के अंदर दस्तावेजों की जांच-पड़ताल कर रही है। सभी कागजातों की छानबीन कर रही है। सुरक्षा को लेकर मौक पर जवान तैनात किए गए हैं। ईडी की टीम किस मामलों को लेकर यह कार्रवाई कर रही है कि, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है।

ईडी रेड के बाद कांग्रेस कर सकती है प्रदर्शन

केके चंद्रवंशी के घर पर छापेमारी के बाद से छत्तीसगढ़ की राजनीतिक फिजा फिर गरमा सकती है। कांग्रेस फिर विरोध प्रदर्शन कर सकती है। फिलहाल ईडी की टीम केके चंद्रवंशी के निवास में कागजों की छानबीन कर रही है। ईडी की जांच जारी है। खबर लिखे जाने तक यह मालूम नहीं चल सका है कि जांच के दौरान क्या-क्या सामने आया? फिलहाल, आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि मामले क्या है।

कमर्शियल एलपीजी सिलिंडर के बढ़े दाम, हवाई सफर भी अब महंगा

■ तेलकंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी पर बढ़ाए 9.50 से 11.50 रुपए दाम

नईदिल्ली ए.। तेल विपणन कंपनियों ने सितंबर 2026 में कमर्शियल एलपीजी सिलिंडर के दाम बढ़ा दिए हैं। 19 किलोग्राम वाले सिलिंडर की कीमतों में प्रमुख शहरों में 9.50 रुपये से 11.50 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है। वहीं, घरेलू उड़ानों के लिए विमान ईंधन यानी एटीएफ की कीमत भी बढ़ी है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के सूत्रों के अनुसार, एटीएफकी कीमत 6.28 रुपये प्रति लीटर बढ़कर 121.28 रुपये प्रति लीटर हो गई है। इससे पहले यह 115 रुपये प्रति लीटर थी।

5 किलोग्राम वाले गैर-घरेलू एलपीजी सिलिंडर की कीमत भी 2 रुपये बढ़ी है। इसकी कीमत 762 रुपये से बढ़कर 764 रुपये प्रति सिलिंडर हो गई है। वहीं, 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलिंडर के दाम लगातार तीसरे महीने स्थिर हैं। सितंबर में दो लगातार महीनों की कटौती के बाद पहली बार कमर्शियल एलपीजी के दाम बढ़ाए गए हैं। सबसे ज्यादा 11.50 रुपये की बढ़ोतरी कोलकाता में हुई है। इसके अलावा भुवनेश्वर, हैदराबाद और पटना में भी कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी हुई है।

दाम बढ़ाने पर कांग्रेस ने केन्द्र पर साधा निशाना

कांग्रेस ने कमर्शियल एलपीजी सिलिंडर की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, जनता पर 'महंगाई मैन' मोदी का हंटर फिर चला है। अब कमर्शियल एलपीजी सिलिंडर 10 रुपए महंगा कर दिया। सिर्फ8 महीने में कमर्शियल सिलिंडर के दाम करीब 1,200 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। जी हां, 8 महीने में 1,200 रुपये महंगा। कांग्रेस ने आगे कहा, महंगाई मैन मोदी का फंडा साफ है- जनता से वसूली करो, दोस्त की तिजोरी भरो।

आतंकवाद किसी के लिए रणनीतिक संपत्ति नहीं हो सकता': एससीओ में पीएम मोदी का सख्त संदेश

नईदिल्ली ए.। शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को लेकर सख्त संदेश दिया। उन्होंने आतंकवाद के पूरे तंत्र को खत्म करने की जरूरत बताई और कहा कि इस गंभीर मुद्दे पर दोहरे मापदंड की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। बिश्केक में आयोजित शिखर सम्मेलन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और एससीओ के अन्य नेताओं की मौजूदगी भी रही।

पीएम मोदी ने कहा, हमें एक आवाज में कहना चाहिए कि इस गंभीर मुद्दे पर दोहरे मापदंड की कोई जगह नहीं हो सकती। जो देश आतंकवाद को अपनी नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं और आतंकवादियों को पनाह और समर्थन देते हैं, उन्हें स्पष्ट संदेश दिया जाना चाहिए कि आतंकवाद किसी के लिए रणनीतिक संपत्ति नहीं हो सकता।

पीएम मोदी ने यह बात बैठक में हुई गोलमेज चर्चा के दौरान कही। इस बैठक में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के अलावा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन, बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको, कजाखस्तान के राष्ट्रपति कासिम-जोमार्ट टोकायेव, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव और ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन शामिल हुए।

सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा-2025 का रिजल्ट जारी, 608 अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिये सलेक्ट

■ 21 सितंबर से होगा साक्षात्कार

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) ने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2025 के परिणाम घोषित कर दिये हैं। लिखित परीक्षा परिणाम के आधार पर कुल 608 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए चयनित किया गया है। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2025 के साक्षात्कार 21 सितंबर 2026 से शुरू होने की उम्मीद है। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2025 के लिखित परीक्षा का परिणाम और इंटरव्यू के लिए चिन्हित अभ्यर्थियों की सूची छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर उपलब्ध है। आयोग ने अभ्यर्थियों से वेबसाइट का नियमित अवलोकन करते रहने की अपील की है।

राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2025 की लिखित परीक्षा 6, 7, 8 और 9 जून 2026 को ली गई थी। अब इसके लिये 608 उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए सलेक्ट किया गया है। साक्षात्कार के लिए चिन्हित सभी अभ्यर्थियों को विज्ञापित पदों की अग्रमान्यता आयोग की वेबसाइट से ऑनलाइन दर्ज करनी होगी। अग्रमान्यता दर्ज करने की तारीख आयोग अलग से जारी करेगा। आयोग के मुताबिक, राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2025 का साक्षात्कार 21 सितंबर 2026 से शुरू होने की संभावना है। साक्षात्कार से संबंधित सूचना, कार्यक्रम और अन्य निर्देश आयोग की वेबसाइट पर अलग से जारी किए जाएंगे।

संपादकीय

फिर-फिर निर्भया कांड

चलती बस में चालक-परिचालक द्वारा यौन हिंसा

एक बार फिर बारह साल पुराने निर्भया कांड की पुनरावृत्ति हुई है। निर्भयाकांड में दिसंबर 2012 में 23 साल की युवती के साथ क्रूरता से गैंगरेप हुआ था, जिसकी बाद में सिंगापुर के एक अस्पताल में मौत हो गई थी। इस घटना के बाद देश में व्यापक आक्रोश उभरा था। यौन हिंसा के खिलाफकानून कठोर किए गए। इस कांड में साल 2020 में चार अपराधियों को फांसी की सजा दी गई थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या सख्त कानून और कठोर सजाओं के बाद ऐसे अपराधों पर अंकुश लगा? दुखद है कि एक बार फिर निर्भयाकांड की पुनरावृत्ति हुई । अकेली नाबालिग लड़की, खाली बस और चलती बस में चालक-परिचालक द्वारा गैंग रेप। उ.प्र. की एक सोलह साल की लड़की किसी बात पर मां की डांट से क्षुब्ध हो घर छोड़कर अपने रिश्तेदार से मिलने नोयडा सेक्टर-63 के लिये चली। लेकिन रात के अंधेरे और बारिश के मौसम की गफ्लत में नोयडा के परी चौक पर उतर गई। सेक्टर-63 जाने के लिये उसने जिस बस को रुकवाया, उसमें बैठे दरिंदों ने बस के वहीं जाने की बात कहकर उसे बैठा लिया। पर्दे लगी स्लीपर बस में लड़की के बैठते ही परिचालक ने उससे छेड़छाड़ शुरू कर दी। चालक-परिचालक ने दुराचार किया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। करीब 47 किलोमीटर के सफ्र में उसके साथ यौन हिंसा हुई। अपराधी उसे कश्मीरी गेट के निकट रिंग रोड में छोड़कर फ्रार हो गए। किशोरी ने साहस दिखाते हुए रात ही में कश्मीरी गेट पुलिस को वारदात की सूचना दी। पुलिस ने इस मामले में टीम बनाकर पड़ताल की। बस की पहचान व रूट की जानकारी सीसीटीवी कैमरों के जरिये की गई। चालक-परिचालक को तिमारपुर की बस पार्किंग से गिरफ्तार किया गया। फोरेंसिक जांच के लिये बस को भी कब्जे में लिया गया है। लेकिन सवाल है कि चार अगस्त की घटना को पुलिस ने क्यों पर्दे में रखा? आखिर क्यों हादसे की सार्वजनिक जानकारी 31 अगस्त को मीडिया को दी गई?

> “ पर्दे लगी स्लीपर बस में लड़की के बैठते ही परिचालक ने उससे छेड़छाड़ शुरू कर दी। चालक-परिचालक ने दुराचार किया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। करीब 47 किलोमीटर के सफ्र में उसके साथ यौन हिंसा हुई। अपराधी उसे कश्मीरी गेट के निकट रिंग रोड में छोड़कर फ्रार हो गए। किशोरी ने साहस दिखाते हुए रात ही में कश्मीरी गेट पुलिस को वारदात की सूचना दी। पुलिस ने इस मामले में टीम बनाकर पड़ताल की।

वहीं दूसरी ओर इंसान के पतन की पराकाष्ठा दिल्ली के बवाना इलाके में सामने आई, जहां स्कूल बस चालक को नर्सरी की एक बच्ची का यौन उत्पीड़न करने पर गिरफ्तार किया गया है। घटना 19 अगस्त को सामने आई जब नर्सरी की छात्रा के परिजनों ने उसके निजी अंगों पर चोट के निशान देखे। बच्ची ने अपनी मां को स्कूल के एक गंदे अंकल के बारे में बताया जो उसे चॉकलेट देता था। परिजनों द्वारा पुलिस को सूचित करने के बाद बस चालक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। शुरुआती जांच के अनुसार बच्ची से चार बार यौन दुर्व्यवहार किया गया था। किसी सभ्य समाज को शर्मसार करने वाली ये घटनाएं जहां समाज में भरोसे को तोड़ती हैं, वहीं कानून व्यवस्था के प्रश्न को भी उठाती हैं। इन मुद्दों पर राजनीति भी जमकर शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि डबल इंजन सरकार में दिल्ली रेप कैपिटल बनती जा रही है।

इसके बावजूद कि दिल्ली में एक महिला मुख्यमंत्री हैं। वहीं कुछ राजनीतिक दल आरोप लगा रहे हैं कि जनता की सुरक्षा व अपराध रोकने के कार्य के बजाय पुलिस पर अन्य कार्यों का बोझ डाला जा रहा है। वहीं सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि पुलिस ने मामले की तह तक जाकर अपराधियों को समय रहते गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई में तेजी दिखायी है। साथ ही लोगों से अपील की है कि वे जागरूक रहें और ऐसी घटनाओं की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। लेकिन मुख्य सवाल यह है कि भारत में यौन लिप्साओं के विस्फोट की असली वजह क्या है? क्यों किन्हीं कमजोर स्थितियों में महिला, लड़की व बच्ची की उम्र का भी लिहाज न कर, यौन हिंसा का शिकार बनाया जा रहा है? हमारा समाज पतनोन्मुखी क्यों होता जा रहा है? क्या यौन अपराधों के मूल में मोबाइल में इंटरनेट के जरिये परोसी जा रही यौन उत्तेजक सामग्री है? देश के समाज विज्ञानियों को इस गंभीर प्रश्न पर मंथन करना होगा।

मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में महिलाओं के सम्मान, स्वावलंबन और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में निरंतर पहल

छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान मातृशक्ति के सम्मान और नारी शक्ति के प्रति आदर की परंपरा से जुड़ी हुई है। मां दंतेश्वरी, मां बम्लेश्वरी, मां महामाया और मां चंद्रहासिनी की आस्था से लेकर माता कौशल्या की धरती तक, छत्तीसगढ़ में मातृशक्ति सदैव सामाजिक जीवन के केंद्र में रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा, आर्थिक सशक्तीकरण और स्वावलंबन को प्राथमिकता देते हुए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन कर रही है। वर्ष 2026 को 'महतारी गौरव वर्ष' के रूप में मनाया जाना इसी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली सरकार के 30 माह के कार्यकाल में महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए महतारी वंदन योजना महत्वपूर्ण पहल के रूप में सामने आई है। योजना के अंतर्गत प्रदेश की करीब 68 लाख विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की जा रही है। इससे महिलाओं को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ परिवार के आर्थिक निर्णयों में अधिक भागीदारी का अवसर मिल रहा है।

एल.डी.मानिकपुरी,
सहायक जनसंपर्क अधिकारी

रक्षाबंधन के पावन पर्व के अवसर पर राज्य सरकार ने महतारी वंदन योजना की 31वीं किस्त की राशि का अंतरण किया। 25 अगस्त को बालोद जिले में आयोजित कार्यक्रम में करीब 68 लाख महिलाओं के बैंक खातों में लगभग 631 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की गई। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि सरकार की मंशा है कि प्रदेश की माताएं-बहनें आर्थिक रूप से सशक्त बनें, अपने छोटे-बड़े निर्णय स्वयं ले सकें और अपने त्योहारों को पूरे उत्साह एवं सम्मान के साथ मना सकें। रक्षाबंधन से पहले खातों में पहुंची यह राशि महिलाओं के लिए आर्थिक संबल के साथ पर्व की खुशियों में सरकार की सहभागिता का संदेश भी लेकर आई।

'स्नेह की डोर' कार्यक्रम में दिखा आत्मीयता और सम्मान का भाव

विगत दिनों रक्षाबंधन के अवसर पर रायपुर में आयोजित 'स्नेह की डोर' कार्यक्रम में स्कूली बेटियों, दिव्यांग बेटियों और महिला स्व-सहायता समूहों की दीदियों ने केंद्रीय सुरक्षा बलों, सेना और पुलिस के जवानों की कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधे। कार्यक्रम में सुरक्षा बलों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का भाव दिखाई दिया। कार्यक्रम का भावुक क्षण उस समय आया, जब वर्ष 2017 में रक्षाबंधन के ठीक एक दिन पूर्व नक्सली मुठभेड़ में वीरगति को प्राप्त हुए शहीद उपनिरीक्षक युगल किशोर वर्मा की धर्मपत्नी माधुरी वर्मा ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की कलाई पर राखी बांधी।

प्रदेश की बहनों के लिए सुरक्षा और विश्वास का सबसे बड़ा उपहार

इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राखी का यह धागा भाई-बहन के स्नेह के साथ-साथ शहीद परिवार के विश्वास और अपनत्व का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद के आतंक से मुक्त कराने के लिए सुरक्षा बलों ने अदम्य साहस का परिचय दिया है। अनेक जवानों ने राष्ट्र और प्रदेश की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सलवाद के अंत की ओर बढ़ता छत्तीसगढ़ प्रदेश की बहनों के लिए सुरक्षा और विश्वास का सबसे बड़ा उपहार है। सरकार का प्रयास है कि नक्सल हिंसा के कारण किसी बहन का सुहाग न उजड़े, किसी मां को अपना बेटा न खोना पड़े और किसी बहन को अपने भाई की सुरक्षा की चिंता न सताए।

महिला स्व-सहायता समूहों से बढ़ा आत्मनिर्भरता का दायरा

राज्य में महिला स्व-सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने का कार्य निरंतर किया जा रहा है। प्रदेश में 2 लाख 42 हजार से अधिक महिला स्व-सहायता समूहों से करीब 30 लाख महिलाएं जुड़ी हुई हैं। लखपति दीदी अभियान के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार और आय के स्थायी साधनों से जोड़ने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। प्रदेश में 13 लाख 85 हजार महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। इससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उनकी भागीदारी भी बढ़ी है। महिला स्व-सहायता समूहों की महिलाएं स्थानीय स्तर पर विभिन्न उत्पादों का निर्माण एवं विपणन कर रही हैं।

प्रदेशभर से मिला मुख्यमंत्री को बहनों का स्नेह

महतारी वंदन योजना की राशि रक्षाबंधन से पहले प्राप्त होने पर प्रदेश के विभिन्न जिलों की महिलाओं ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। सुकमा से कोरिया और राजनांदगांव से रायगढ़ तक प्रदेश के विभिन्न अंचलों की महिलाओं ने मुख्यमंत्री के प्रति स्नेह और विश्वास व्यक्त करते हुए उन्हें बड़े भाई के रूप में सम्मान दिया। महिलाओं ने कहा कि महतारी वंदन योजना से उन्हें अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता मिल रही है। उनमें आत्मविश्वास बढ़ाया है और परिवार की आवश्यकताओं के लिए उन्हें अधिक सक्षम बनाया है।

राज्य सरकार महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन के लिए प्रतिबद्ध

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेश की नारी शक्ति के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि महिलाओं का सम्मान, स्वावलंबन और समृद्धि राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने तथा उन्हें विकास की मुख्यधारा में आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। महतारी वंदन योजना, महिला स्व-सहायता समूहों और लखपति दीदी जैसे प्रयासों से छत्तीसगढ़ में नारी शक्ति को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में नई संभावनाएं तैयार हो रही हैं। रक्षाबंधन के अवसर पर बहनों के खातों में पहुंची सहायता राशि ने इस विश्वास को और मजबूत किया है।

एआई युग में नौकरी मिलने-खोने के यक्ष प्रश्न

डॉ. शशांक द्विवेदी

वैश्विक वित्तीय संस्था नोमुरा की रिपोर्ट के अनुसार, 2022 से अगस्त, 2026 के बीच भारत में एआई से संबंधित करीब 83,100 नौकरियां पैदा हुई, जबकि एआई से जुड़ी 31,921 नौकरियां प्रभावित हुईं। मगर यह निष्कर्ष निकालना खतरनाक होगा कि एआई सिर्फ रोजगार बढ़ा रहा है। एआई को लेकर में सबसे बड़ा डर यही रहा है कि मशीनें इंसानों की नौकरियां छीन लेंगी। चैटबॉट से लेकर जनरेटिव एआई तक, तकनीक जिस तेजी से विकसित हुई है, उसने इस आशंका को और गहरा किया है।

वैश्विक वित्तीय संस्था नोमुरा की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, 2022 से अगस्त, 2026 के बीच भारत में एआई से संबंधित करीब 83,100 नौकरियां पैदा हुईं, जबकि एआई से जुड़ी 31,921 नौकरियां छंटनी या कर्मचारियों की कमी के रूप में प्रभावित हुईं। अर्थात, हर एक प्रभावित नौकरी के मुकाबले लगभग 2.6 नई एआई-संबंधित नौकरियां बनीं। मगर यह निष्कर्ष निकालना खतरनाक होगा कि एआई रोजगार की समस्या समाप्त कर रहा है। एआई नई नौकरियां जरूर बना रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि जिन लोगों की पुरानी नौकरियां जा रही हैं, वही लोग नई नौकरियों में प्रवेश कर पा रहे हों। यही भारत के सामने उभरती सबसे बड़ी रोजगार चुनौती है। नोमुरा के अनुसार, भारत में एआई अपनाने से एक 'दो-स्तरीय रोजगार बाजार' उभर रहा है। एक तरफ अनुभवी कर्मचारियों की मांग बनी हुई है, वहीं दूसरी तरफ प्रेशर्स के लिए अवसर अपेक्षाकृत कम हो रहे हैं। भारतीय आईटी क्षेत्र की 651 कंपनियों पर किए गए आईसीआरआईईआर के सर्वेक्षण में 55 प्रतिशत कंपनियों ने बताया कि उनकी एंट्री-लेवल भर्ती में कमी आई है। इसके मुकाबले मिड-लेवल भर्ती में कमी बताने वाली कंपनियों का अनुपात 25 प्रतिशत और वरिष्ठ स्तर पर केवल 14 प्रतिशत था।

भारत की आर्थिक ताकत का एक बड़ा आधार हर वर्ष कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से निकलने वाली विशाल युवा आबादी है। यदि कंपनियां पहले की तरह बड़ी संख्या में प्रेशर्स को नियुक्त नहीं करतीं तो समस्या केवल बेरोजगारी की नहीं होगी, बल्कि 'करिअर की पहली सीढ़ी' के कमजोर पड़ने की होगी। दरअसल, पारंपरिक कॉर्पोरेट व्यवस्था में एक युवा कर्मचारी सामान्य काम से शुरुआत करता था। वह डेटा तैयार करता था, रिपोर्ट बनाता था, बेसिक कोड लिखता था, गुणवत्ता जांच करता था, ग्राहक सेवा संभालता था और धीरे-धीरे अनुभव हासिल करके जिम्मेदार पदों तक पहुंचता था। एआई इन शुरुआती कार्यों का एक बड़ा हिस्सा तेजी से करने लगा है।

नोमुरा ने स्टाफिंग फर्म स्फेनो के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि भारतीय आईटी कंपनियों की नेट हायरिंग वित्त वर्ष 2021-22 में लगभग छह लाख थी, जो वित्त वर्ष 2025-26 में घटकर करीब 1.40 लाख रह गई। कंपनियां बड़े पैमाने पर कैंपस भर्ती करने के बजाय कम, लेकिन कुशल कर्मियों को प्राथमिकता दे रही हैं। यहां एआई को अकेला दोषी मानना भी उचित नहीं होगा। वैश्विक मांग, आईटी उद्योग का पुनर्गठन, लागत नियंत्रण और ऑटोमेशन जैसे कई कारक इस बदलाव के पीछे हैं। लेकिन एआई ने इस परिवर्तन की गति निश्चित रूप से बढ़ा दी है।

लेकिन अगर एआई नई नौकरियां बना रहा है तो वे नौकरियां किसके लिए हैं? एआई मॉडल विकसित करने वाले इंजीनियर, डेटा विशेषज्ञ, मशीन लर्निंग विशेषज्ञ, एआई ट्रेनर, डेटा एनोटेटर, भाषा विशेषज्ञ, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ और एआई सिस्टम को व्यवसाय से जोड़ने वाले पेशेवरों की मांग बढ़ रही है। नोमुरा के एशियाई अध्ययन में एआई से संबंधित नई नौकरियों का 90 प्रतिशत से अधिक हिस्सा टेक्नोलॉजी क्षेत्र में केंद्रित था। इसका अर्थ यह है कि भारत के सामने अब केवल 'कितनी नौकरियां?' का सवाल नहीं है। महत्वपूर्ण प्रश्न है—'किस कौशल वाली कितनी नौकरियां?' आने वाले वर्षों में एआई का असली मुकाबला उन कर्मचारियों के बीच होगा जो एआई का इस्तेमाल करना जानते हैं और उन कर्मचारियों के बीच जो इसे केवल अपने रोजगार के लिए खतरा मानते हैं। एक अकाउंटेंट जो एआई आधारित विश्लेषण, ऑटोमेशन और डेटा टूल का उपयोग कर सकता है, उसकी उपयोगिता उस अकाउंटेंट से अधिक हो सकती है जो केवल पारंपरिक तरीके से काम करता है। इसी तरह एक पत्रकार जो शोध, डेटा विश्लेषण और प्रारंभिक ड्राफ्टिंग के लिए एआई का प्रभावी इस्तेमाल कर सकता है, वह तकनीक से प्रतिस्थापित होने के बजाय तकनीक की उत्पादकता बढ़ाने वाला पेशेवर बन सकता है। इसलिए भारत को 'एआई के साथ रोजगार' की रणनीति बनानी होगी।

निस्संदेह, एआई युग में रोजगार का स्वरूप बदलने जा रहा है। संभव है कि भविष्य में एक कर्मचारी वही काम करे जो आज तीन लोग करते हैं, लेकिन साथ ही ऐसे नए काम भी पैदा हों जिनकी आज कल्पना तक नहीं की गई है। आज देश के पास विशाल युवा आबादी, मजबूत आईटी उद्योग, अंग्रेजी सहित अनेक भाषाओं की क्षमता और दुनिया के लिए डिजिटल सेवाएं देने का अनुभव है। यदि इन ताकतों को एआई कौशल के साथ जोड़ा जाए तो भारत एआई-आधारित रोजगार का वैश्विक केंद्र बन सकता है।

लेखक टीएसएससी, परियोजना प्रबंधक हैं।

न्याय का उद्देश्य ही विफल

अजीत द्विवेदी

पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव न तो रद्द होगा और न इसे दोबारा कराने के बारे में कोई सोचेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जो पूछा वह अपने आप में बड़ी बात है। सर्वोच्च अदालत ने चुनाव आयोग से पूछा कि 'क्या वह बंगाल में नए सिरे से चुनाव कराने का आदेश दे सकता है'? चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के दौरान लाखों लोगों के नाम काटे जाने के मामले में सुनवाई करते हुए यह सवाल पूछा और उसके बाद अदालत ने विधानसभा सीटों की हार जीत के अंतर सहित दूसरी कई चीजों का ब्योरा दाखिल करने को कहा है। सुनवाई के दौरान तृणमूल कांग्रेस के वकील ने 31 सीटों का ब्योरा दिया और कहा कि उन सीटों पर भाजपा की जीत का अंतर एसआईआर में कटे वोट से ज्यादा है। मिसाल के तौर पर विधानसभा क्षेत्र संख्या 145 यानी दक्षिण 24 परगना की सतगछिया सीट पर भाजपा सिर्फ 401 वोट से जीती, जबकि वहां 8,785 वोट कटे थे।

बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले का अंत नतीजा क्या निकलेगा यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। चुनाव तो दोबारा नहीं होंगे। लेकिन यह बहुत गंभीर मामला है। पहली नजर में ऐसा लग रहा है कि एसआईआर के दौरान मनमाने तरीके से नाम काटने का चुनाव नतीजों पर असर हुआ है। इसका कारण सिर्फ यह नहीं है कि भाजपा की जीती 31 सीटें ऐसी हैं, जहां जीत का अंतर एसआईआर में कटे वोट से कम है। ऐसी बहुत सी सीटें तृणमूल कांग्रेस ने भी जीती हैं। इसलिए एसआईआर के असर का आकलन करने का यह एकमात्र आधार नहीं हो सकता है। इसके दूसरे कई आधार हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान सामने आ रहे आंकड़ों में दिख रहे हैं।

असल में सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर सुनवाई के दौरान कुछ बहुत दिलचस्प आंकड़े सामने आए। इसमें सबसे दिलचस्प आंकड़ा तार्किक विसंगति के आधार पर नाम काटने का है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दौरान एक तार्किक विसंगति की श्रेणी बनाई थी, जिसके तहत 27 लाख से ज्यादा लोगों के नाम काटे गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इन सब लोगों की सुनवाई के लिए न्यायाधिकरण बनाने का आदेश दिया था और उस आदेश पर 19 न्यायाधिकरण बनाए गए थे। तार्किक विसंगति वाले 27 लाख लोगों के अलावा 11 लाख अन्य लोगों ने भी बाद में इन न्यायाधिकरणों के सामने अपील दायर की और नाम काटे जाने के फैसले का विरोध किया।

सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार, 25 अगस्त को हुई सुनवाई में पता चला कि अभी तक सिर्फ 83 हजार नामों की सुनवाई न्यायाधिकरणों में हुई है। इसकी रफ्तार तो निराश करने वाली है लेकिन नतीजे हैरान करने वाले हैं। जिन 83 हजार लोगों के दस्तावेज जांचे गए और आपत्ति सुनी गई उनमें से 75,443 लोगों की आपत्ति सही पाई गई और न्यायाधिकरणों ने उनका नाम मतदाता सूची में शामिल करने का आदेश दिया। सोचें, यह कितनी बड़ी बात है! अपील करने वाले लगभग 90 फीसदी लोगों की आपत्ति जायज है। इसका हिसाब लगाएं तो लगभग 34 लाख लोगों के नाम बिना किसी आधार के काट कर उनको मताधिकार से वंचित कर दिया गया। यह ध्यान रखने की बात है कि चुनाव जीतने वाली भाजपा और हारने वाली तृणमूल कांग्रेस के बीच 31 लाख वोट का अंतर है।

मतदाता सूची का पुनरीक्षण कोई नई बात नहीं है और न कोई गैरजरूरी एक्सरसाइज है। ऐसा होना चाहिए और निश्चित रूप से 'एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड और डुप्लीकेट' इन चार श्रेणियों के लोगों के नाम कटने चाहिए। सभी राज्यों में इन चार आधारों पर नाम कट रहे हैं और उसमें जिसको आपत्ति होती है वह अपनी आपत्ति दर्ज कराता है, दस्तावेज पेश करता है और सुधार कराता है। लेकिन चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में तार्किक विसंगति की एक अलग श्रेणी बना दी और उसमें 27 लाख से ज्यादा नाम काट दिए। हकीकत यह है कि नाम काटने के लिए जो तार्किक विसंगतियां बताई गई हैं वो बेहद अतार्किक हैं तभी जिनके नाम कटे हैं वे दस्तावेज लेकर न्यायाधिकरण के सामने पेश हो रहे हैं और अपना नाम मतदाता सूची में वापस दर्ज करा रहे हैं।

इससे यह सवाल उठता है कि क्या चुनाव आयोग इस बात को जानता था कि तार्किक विसंगति के कारण जिनका नाम काट रहे हैं वे जेनुइन मतदाता हैं और दस्तावेज दिखा कर वापस नाम शामिल करा सकते हैं? अगर यह बात साबित होती है तो इसका अर्थ होगा कि चुनाव आयोग ने नतीजों को प्रभावित करने के लिए जान बूझकर इस तरह का काम किया और इससे चुनाव आयोग की साख पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी।

यह मानना थोड़ा मुश्किल है कि तार्किक विसंगति के कारण नाम काटने से पहले चुनाव आयोग को यह बात समझ में नहीं आई हो कि इनके दस्तावेज सही हैं। आखिर ऐसे 90 फीसदी लोगों के नाम सही पाए जा रहे हैं। अगर चुनाव आयोग को यह बात समझ नहीं आई तो यह उसकी अक्षमता का बड़ा सबूत है और अगर समझ में आई फिर भी नाम काटा तो उसकी साख मिट्टी में मिलती है। सो, इस मामले का जो भी नतीजा निकलेगा वह आयोग के लिए अच्छा नहीं होगा।

हालांकि इसके बावजूद पश्चिम बंगाल का चुनाव रद्द नहीं होगा और न दोबारा चुनाव होगा। फिर भी अगर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में चुनाव आयोग एक्सपोज होता है और मताधिकार से वंचित किए गए लोगों को राहत मिलती है तो उसका बड़ा असर होगा। यह समझने की जरुरत है कि मतदाता सूची से नाम कटने के बाद बंगाल के लाखों लोग सिर्फ मताधिकार से वंचित नहीं हुए हैं, बल्कि उनको बुनियादी नागरिक सुविधाओं से भी वंचित किया जा रहा है। उनकी नागरिकता पर सवाल उठाया जा रहा है। उन्हें सरकार से मिलने वाली सुविधाएं रोकी जा रही हैं और नागरिकता प्रमाणित करने को कहा जा रहा है। इसलिए बंगाल के नतीजे भले नहीं बदलें लेकिन चुनाव आयोग की मनमानी का शिकार हुए लाखों लोगों को राहत जरूर मिलनी चाहिए और वह राहत जितनी जल्दी मिले उतना अच्छा होगा। उच्च अदालतों ने खुद माना है कि न्यायाधिकरण में मौजूदा रफ्तार से सुनवाई में 21 साल लगेंगे। इससे तो न्याय का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। इसलिए इसमें तेजी लाने की जरुरत है।

विरोधी खेमों पर अब कोई असर नहीं

हकीकत से कटे नैरेटिव्स का अपना जीवनकाल होता है। जब उनका सामना विपरीत होते जमीनी हालात से होता है, तो उनमें दरारें पड़ने लगती हैं। ज़ेन-ज़ी का तेवर उन्हीं हालात का नतीजा है। भारत का राजनीतिक विमर्श काफी पहले शालीनता की हदें तोड़ चुका है, इसलिए इसमें नए अपशब्दों के जुड़ने पर शायद ही किसी को एतराज होता है। तीखे ध्रुवीकरण की मौजूदा सूरत में किसी नेता की टिप्पणियों को गरिमा-विहीन या मर्यादा के खिलाफ बता कर उसे घेरने की रणनीति का विरोधी खेमों पर अब कोई असर नहीं होता। कई वर्षों तक इस नई स्थिति का लाभ भाजपा ने उठाया। भाजपा नेताओं को लेकर कुछ हलकों से तब भी ऐसे शब्द बोले जाते थे, लेकिन तब कथानक पर भाजपा इकॉ-सिस्टम का इतना दबदबा था, वे शब्द बोलने वाले को ही भारी पड़ जाते थे। लेकिन यह बदले माहौल का ही संकेत है कि ऐसे लफ्ज़ अब जनमत के एक बड़े हिस्से में नया राजनीतिक कथानक गढ़ने का काम करने लगे हैं।

भाजपा काफी समय तक विपक्षी नेताओं को प्रहसन-पात्र के रूप में पेश सियासी फायदे उठाती रही, मगर अब सोशल मीडिया- खासकर रील्स के इस्तेमाल से वैसी ही छवि उनके शीर्ष नेताओं को पेश की जा रही है, जिसे एक बड़ा श्रोता वर्ग मिल रहा है। बेशक, यह स्थिति लाने में ज़ेन-ज़ी के आंदोलनों ने बड़ी भूमिका निभाई है। भाजपा के सामने सवाल खड़ा है कि कहानी ऐसे क्यों पलटने लगी है? वे आत्म-मंथन करें, तो शायद उन्हें आभास होगा कि यथार्थ से कटे कथानकों का अपना जीवनकाल होता है। जब उनका सामना विपरीत होते जमीनी हालात से होता है, तो उनमें दरारें पड़ने लगती हैं।

ज़ेन-ज़ी का तेवर उन्हीं हालात का नतीजा है। हिंदुत्व की पहचान के साथ 'विश्व गुरु' की हैसियत दिलाने के वादों से वह छली गई महसूस कर रही है, तो उसकी वजहें हैं। ये पीढ़ी 'मेक इन इंडिया', 'नया भारत', 'देश बदल रहा है', 'अमृत काल', 'विकसित भारत' जैसे नारों को सुनते हुए जब बड़ी हुई, तो उसने पाया कि असल में उसके पास आगे बढ़ने के पहले जितने अवसर भी उपलब्ध नहीं हैं। तो वह हिसाब मांग रही है। इसका जवाब 'सप्तधारा' जैसे नए नैटेरिव गढ़ कर नहीं दिया जा सकता। ना ही 'दिमागी नक्सलियों' को अलग-थलग करने जैसे एलान नई परिस्थितियों में अपेक्षित भय पैदा कर सकेंगे।

ITR फाइल 500/-
Whatsapp पर बनवाएँ
Income Tax फाइल, GST रजिस्ट्रेशन, TDS रिफंड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट
CMA DATA, MSME, BALANCE SHEET, फूड लाइसेंस
हमारे Tax Expert आपकी मदद हेतु तैयार है।
www.onlytds.com
सम्पर्क - शेखर गुप्ता 9300755544 - 8878655544

श्रीकंचनपथ
भिलाई-दुर्ग

प्रिंट और डीजिटल मीडिया में
सभी प्रकार के विज्ञापन
के लिए
संपर्क करे
Mob.-:
9303289950
7987166110

प्रमुख खबरें...

जनदर्शन में 7 नागरिकों ने रखी समस्याएं, त्वरित निराकरण के दिए निर्देश

भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा नागरिकों की समस्याओं एवं मांगों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रत्येक सोमवार को जनदर्शन आयोजित किया जाता है। इसी क्रम में निगम आयुक्त सुरुचि सिंह के निर्देशानुसार निगम सभागार कक्ष में आयोजित जनदर्शन में 7 नागरिकों ने उपायुक्त नरेन्द्र कुमार बंजारे के समक्ष अपनी मांग एवं शिकायतें प्रस्तुत कीं। जनदर्शन में नागरिकों ने विभिन्न मूलभूत सुविधाओं, विकास कार्यों एवं व्यक्तिगत समस्याओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। उपायुक्त ने नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को प्राप्त आवेदनों का परीक्षण एवं आवश्यकतानुसार स्थल निरीक्षण कर नियमानुसार त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए।

जिले में अब तक 668.8 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज

दुर्ग। जिले में 1 जून 2026 से 31 अगस्त 2026 तक 668.8 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है। कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 जून से अब तक सर्वाधिक वर्षा 850.7 मिमी तहसील पाटन में तथा न्यूनतम 486.3 मिमी. तहसील धमधा में दर्ज की गई है। इसके अलावा तहसील दुर्ग में 782.5 मिमी, तहसील बोरी में 624.9 मिमी, तहसील भिलाई-3 में 720.4 मिमी और तहसील अहिवारा में 548.0 मिमी वर्षा दर्ज की गई है। 31 अगस्त 2026 को तहसील दुर्ग में 16.7 मिमी, तहसील धमधा में 10.6 मिमी, तहसील पाटन में 29.6 मिमी, तहसील बोरी में 8.4 मिमी, तहसील भिलाई 3 में 15.2 मिमी और तहसील अहिवारा में 10.8 मिमी वर्षा दर्ज की गई है।

दुर्ग में बकेट क्लेम पंजीयन में आई तेजी

दुर्ग। कलेक्टर अभिजीत सिंह द्वारा एग्रीस्टेक एवं बकेट क्लेम पंजीयन को प्राथमिकता देते हुए इसकी नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। किसानों के पंजीयन एवं संबंधित प्रक्रियाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप जिले में बकेट क्लेम के निराकरण की प्रक्रिया में लगातार प्रगति हो रही है। 27 अगस्त 2026 तक जिले में कुल 1,21,878 बकेट क्लेम पूर्ण किए जा चुके हैं। जिले में कुल 4,59,909 बकेट क्लेम दर्ज हैं। तहसील स्तर पर बोरी 57.19 प्रतिशत क्लेम पूर्ण कर जिले में प्रथम स्थान पर है। इसके बाद धमधा में 49.93 प्रतिशत, अहिवारा में 39.97 प्रतिशत और पाटन में 38.59 प्रतिशत क्लेम पूर्ण किए जा चुके हैं।

भिलाई-3 में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय तथा परिवार न्यायालय कैम्प कोर्ट का वर्चुअल उद्घाटन

■ न्यायिक सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। नागरिकों के निकट न्याय को पहुंचाने तथा न्यायिक सुविधाओं का विस्तार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में आज भिलाई-3 में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय तथा परिवार न्यायालय (कैम्प कोर्ट-अतिरिक्त बैठक) का वर्चुअल उद्घाटन किया गया। माननीय न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधिपति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर ने माननीय न्यायमूर्ति नरेश कुमार चंद्रवंशी, पोर्टफोलियो न्यायाधीश, जिला दुर्ग की गरिमामयी उपस्थिति में भिलाई-3 स्थित जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय तथा परिवार न्यायालय (कैम्प कोर्ट-अतिरिक्त बैठक), जिला दुर्ग का वर्चुअल उद्घाटन किया।

यह उद्घाटन भिलाई-3 क्षेत्र में न्यायिक सेवाओं की उपलब्धता को अधिक सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय तथा परिवार न्यायालय कैम्प कोर्ट-अतिरिक्त बैठक के प्रारंभ होने से क्षेत्र के नागरिकों को न्यायिक कार्यवाहियों के लिए अधिक सुविधाजनक एवं निकटस्थ न्यायिक मंच उपलब्ध होगा। उद्घाटन के बाद न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने अपने उद्बोधन में न्यायिक सेवाओं के विस्तार से जोड़ते हुए अपने विचार व्यक्त किए। भिलाई-3 में न्यायिक सुविधाओं का यह विस्तार न्याय वितरण प्रणाली में सुगमता, पहुंच एवं नागरिक-केंद्रित न्याय की भावना को सुदृढ़ करने की दिशा में एक कदम है। विशेष रूप से, परिवार न्यायालय कैम्प कोर्टदृअतिरिक्त बैठक के प्रारंभ होने से पारिवारिक विवादों से संबंधित मामलों में संलग्न पक्षकारों को स्थानीय स्तर पर न्यायिक सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

कार्यक्रम का शुभारंभ निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार गणमान्य अतिथियों के आगमन के साथ हुआ। तत्पश्चात के. विनोद कुजूर, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग ने स्वागत उद्बोधन में कहा कि भिलाई-तीन एक महत्वपूर्ण एवं तीव्र गति से विकसित हो रहा क्षेत्र है, जहां बढ़ती हुई जनसंख्या तथा विविध प्रकार की विधिक आवश्यकताएं हैं। समर्पित न्यायालयों की स्थापना के पीछे की परिकल्पना एवं मार्गदर्शक विचार माननीय मुख्य न्यायाधिपति के दूरदर्शी नेतृत्व एवं मार्गदर्शन से अत्यधिक प्रेरित रहे हैं। अत: भिलाई-तीन में न्यायालयों की स्थापना, अधिक सुगम, उत्तरदायी एवं नागरिक-केंद्रित न्याय वितरण प्रणाली के संबंध में माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय की परिकल्पना का प्रतिबिंब है।

वर्चुअल उद्घाटन के तत्काल पश्चात् भिलाई-3 में प्रारंभ किए जा रहे जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय तथा परिवार न्यायालय से संबंधित एक संक्षिप्त वीडियो प्रदर्शित किया गया। वीडियो के माध्यम से प्रस्तावित न्यायिक सुविधा तथा उसकी प्रकृति की एक झलक उपस्थितजनों के समक्ष प्रस्तुत की गई। यह प्रस्तुति केवल एक नई न्यायिक सुविधा के संबंध में जानकारी मात्र नहीं थी, बल्कि यह न्याय वितरण प्रणाली को लोगों के और अधिक निकट लाने की दिशा में एक नई शुरुआत का दृश्यात्मक परिचय भी बनी।

न्याय को लोगों के और पास लाने एक महत्वपूर्ण कदम

कार्यक्रम के अंत में, सुमन एक्का, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, दुर्ग ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। उन्होंने माननीय मुख्य न्यायाधिपति, न्यायिक अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों तथा कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान देने वाले सभी संबंधित व्यक्तियों के प्रति आभार व्यक्त किया। उल्लेखनीय है कि भिलाई-3 में इस नवीन न्यायिक सुविधा का प्रारंभ न्याय को लोगों के और निकट लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पहल न केवल न्यायिक अधोसंरचना के विस्तार को प्रतिबिंबित करती है, बल्कि बदलते समय के अनुरूप एक सुचारु, सुगम एवं नागरिक-केंद्रित न्याय वितरण प्रणाली के प्रति प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करती है।

देहदान प्रक्रिया में पारदर्शिता और व्यवस्था में सुधार लाने आगे आए विधायक रिकेश सेन

दुर्ग कलेक्टर को पत्र लिखकर नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश

श्रीकंचनपथ न्यूज

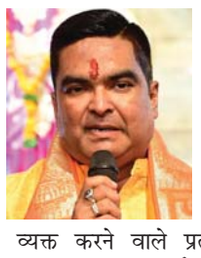

भिलाई। वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रिकेश सेन ने देहदान की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और सुगम बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। उन्होंने जिला दुर्ग के कलेक्टर को पत्र सौंप कर जिले में देहदान के लिए जिला स्तरीय व्यवस्था बनाने और एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने निर्देश दिए हैं।

विधायक रिकेश सेन ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि देहदान मानवता और चिकित्सा जगत की सेवा का अत्यंत पवित्र और पुनीत संकल्प है। जिले में अनेक नागरिक मृत्यु उपरांत देहदान करने की इच्छा रखते हैं। इस संवेदनशील प्रक्रिया में दानकर्ता की इच्छा, परिजनों की सही जानकारी और सभी वैधानिक व चिकित्सीय औपचारिकताएं पूरी पारदर्शिता के साथ निष्पादित होनी चाहिए।

विधायक ने अपने पत्र में देहदान की इच्छा व्यक्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का जिला प्रशासन स्तर पर पूर्व पंजीयन/सूचना दर्ज करने की व्यवस्था करने, मृत्यु उपरांत देहदान की प्रक्रिया शुरू करने से पहले प्रशासन द्वारा नामित नोडल अधिकारी को अनिवार्य रूप से सूचित करने का प्रावधान किए जाने, देहदान स्वीकार करने वाली अधिकृत संस्थाओं की सूची और स्पष्ट मानक संचालन प्रक्रिया जारी करने कहा है।

विधायक सेन ने लिखा है कि किसी भी संस्था या संगठन द्वारा जिला प्रशासन की जानकारी और तय वैधानिक प्रक्रिया के बिना देहदान की कार्यवाही न की जाए।

ब्लास्ट फर्नेस के अफसरों के बीच 'सतर्कता संवाद' का आयोजन

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) के सतर्कता विभाग द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2026 के पूर्व आयोजित किए जा रहे सतर्कता जागरूकता अभियान के अंतर्गत ब्लास्ट फर्नेस विभाग के अधिकारियों के लिए पहली बार 'सतर्कता संवाद' कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस वर्ष केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा निर्धारित थीम 'सत्यनिष्ठा से समृद्धि' कार्यक्रम का मुख्य आधार रही। बीएसपी सतर्कता विभाग की इस पहल का नेतृत्व महाप्रबंधक (सतर्कता) रेणु गुप्ता एवं उप महाप्रबंधक (सतर्कता) मो. नौशाद आलम ने किया। इस अवसर पर वरिष्ठ सतर्कता निरीक्षक वीवीएस राव एवं वरिष्ठ सतर्कता निरीक्षक अजय सिंह भी उपस्थित रहे।

संवादात्मक स्वरूप में आयोजित इस कार्यक्रम में ब्लास्ट फर्नेस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों सहित 20 से अधिक अधिकारियों ने सहभागिता की। कार्यक्रम के दौरान क्रय एवं क्रियान्वयन से संबंधित विभिन्न व्यावहारिक चुनौतियों पर विशेष रूप से चर्चा की गई। इसके साथ ही क्रय एवं क्रियान्वयन से जुड़ी अनियमितताओं पर आधारित विभिन्न केस स्टडी पर विचार-विमर्श किया गया।

कार्यक्रम में अधिकारियों ने क्रय एवं क्रियान्वयन की प्रक्रियाओं के दौरान सामने आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों और चुनौतियों को साझा किया। साथ ही, प्रक्रियाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने, कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने तथा दैनिक कार्यों में सतर्कता एवं सत्यनिष्ठा के मानकों को प्रभावी ढंग से अपनाने के लिए अपने सुझाव भी प्रस्तुत किए। इस दौरान विभिन्न विषयों पर खुलकर विचारों का आदान-प्रदान हुआ और संभावित जोखिमों तथा उन्हें कम करने के उपायों पर भी चर्चा की गई। सतर्कता टीम ने कार्यक्रम को सतर्कता अधिकारियों एवं परिचालन अधिकारियों के बीच खुले और रचनात्मक संवाद को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया।

टीम ने कहा कि इस प्रकार के संवादात्मक कार्यक्रम न केवल अधिकारियों को प्रक्रियागत एवं व्यावहारिक चुनौतियों को साझा करने का अवसर प्रदान करते हैं, बल्कि कार्यप्रणाली में पारदर्शिता एवं सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देने में भी सहायक होते हैं। कार्यक्रम की सकारात्मक प्रतिक्रिया को देखते हुए बीएसपी सतर्कता विभाग द्वारा आगामी दिनों में इसी प्रकार के 'सतर्कता संवाद' सत्र अन्य विभागों में भी आयोजित किए जाने की योजना है।

कामधेनु विश्वविद्यालय में प्राध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया तत्काल रोकने की मांग

■ दो साल बाद भर्ती विज्ञापन निरस्त करने पर उठे सवाल

■ आरक्षण रोस्टर में अनियमितता, बैकलॉग पद भी प्रभावित

श्रीकंचनपथ न्यूज

दुर्ग। दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय में जारी सहायक प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक एवं प्राध्यापक बदों की जारी भर्ती प्रक्रिया को तत्काल रोकने की मांग की गई है। पीड़ित पक्ष द्वारा इसकी शिकायत अनुसूचित जनजाति आयोग से करते हुए आशंका जताई गई है कि भर्ती प्रक्रिया के लिए अपनाई जा रही प्रक्रिया से उनके हितों का नुकसान हो सकता है।

उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा 13 जुलाई 2023 में 35 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी हुआ था। लगभग दो साल बाद 16 सितंबर 2025 को उसे निरस्त कर दिया गया। इसकी कोई वजह नहीं बताई गई। इसके बाद 11 फरवरी 2026 को 60 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया गया। शिकायत में कहा गया है कि विभागवार सीट निर्धारण, आरक्षण वर्गीकरण पूरी समिति की औपचारिक बैठक में तय नहीं हुआ। रोस्टर समिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला प्रतिनिधित्व का पूरा ध्यान नहीं रखा गया। इससे आरक्षित वर्गों के पद प्रभावित हो सकते हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि पशुधन फार्म परिसर और पशु चिकित्सा नैदानिक परिसर प्रशासनिक रूप से एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। पदों के विज्ञापन में रोस्टर अलग-अलग लागू किया गया। इसे नियम विरुद्ध बताते हुए चुनौती दी गई है।

बैकलॉग पद भरे बिना भर्ती विज्ञापन जारी

5 मार्च 2019 को जारी विज्ञापन में 42 बैकलॉग पद निकाले गए थे। इनमें से केवल 7 पदों पर नियुक्ति हुई। 35 पद अब भी रिक्त बताए जा रहे हैं। नियमों के अनुसार पहले बैकलॉग पद भरना अनिवार्य होता है उसके बाद अन्य पदों पर भर्ती की जाती है।

औपचारिकताओं को किया दरकिनार

शिकायत में यह भी कहा गया है कि विभागवार सीट निर्धारण, आरक्षण वर्गीकरण पूरी समिति की औपचारिक बैठक में तय नहीं हुआ। रोस्टर समिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला प्रतिनिधित्व का पूरा ध्यान नहीं रखा गया।

पहले पद तय कर लिये, फिर बैठक में अनुमोदन

29.01.2025 से रोस्टर कमेटी गठित की गई और 31.01.2025 को विभिन्न फैकल्टी/विभागों को एक इकाई मानकर अंग्रेजी वर्णानुक्रम में केवल 35 शैक्षणिक पद निर्धारित किये गये। रोस्टर निर्धारित करने की व्यवस्था को 30.07.2025 को कार्यपरिषद की 25वीं बैठक में अनुमोदित किया गया। इस संबंध में आदेश 16.09.2025 को जारी हुआ।

शिकायतकर्ताओं की मांग, बैकलॉग पदों को पहले भरा जाए

शिकायतकर्ताओं ने रोस्टर रजिस्टर, समिति कार्यवाही, विज्ञापन निरस्तीकरण से जुड़े सभी दस्तावेज सार्वजनिक करने की मांग की। शिकायतकर्ताओं ने कहा है कि पहले शेष बैकलॉग पद नियमानुसार भरे जाएं। उसके बाद ही नए पदों पर भर्ती शुरू हो।

बीएसपी में डिजिटल साइनिंग मॉड्यूल का शुभारंभ

■ ग्राहक अनुभव को और बेहतर बनाने मिलेगा लाभ

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र में सेल ऑफर्स के डिजिटल साइनिंग हेतु एक नए मॉड्यूल का शुभारंभ किया गया। कार्यपालक निदेशक (सामग्री प्रबंधन), एके चक्रवर्ती ने 31 अगस्त 2026 को इस्पात भवन में इस डिजिटल साइनिंग मॉड्यूल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक (सामग्री प्रबंधन एवं विपणन), अयान मिश्रा, महाप्रबंधक (विपणन), चैताली दास, सहित विपणन एवं सी एंड आईटी विभाग के अन्य वरिष्ठ कार्यपालक उपस्थित थे।

कार्यपालक निदेशक (सामग्री प्रबंधन), एके चक्रवर्ती ने इस परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए विपणन एवं सीएंड आईटी टीम को बधाई दी। उन्होंने ग्राहक अनुभव को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से इस प्रकार की और अधिक डिजिटल पहलों की संभावनाएं तलाशने की सलाह दी।

वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत एम एंड बीपी विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले सेल ऑफर्स पर मैनुअल हस्ताक्षर किए जाते हैं। इसके पश्चात मेसर्स मेटल जंक्शन (एमजंक्शन) द्वारा भौतिक सेल ऑफर्स विभाग से प्राप्त कर उस पर मैनुअल हस्ताक्षर करवाए जाते हैं तथा हस्ताक्षरित सेल ऑफर्स की सकैंड प्रतियां ग्राहकों को प्रेषित की जाती हैं।

ग्राहक संतुष्टि में वृद्धि तथा कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी, त्वरित एवं सुगम बनाने के उद्देश्य से विपणन एवं व्यवसाय नियोजन विभाग द्वारा सी एंड आईटी विभाग के समन्वय से सेल ऑफर्स के डिजिटल साइनिंग के लिए यह नई पहल विकसित की गई है। इस नए मॉड्यूल के कार्यान्वयन के पश्चात अधिकृत विपणन कार्यपालकों के डिजिटल सिग्नेचर युक्त सेल ऑफर्स सीधे ग्राहकों एवं एमजंक्शन को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित किए जा सकेंगे।

इस मॉड्यूल के विकास में महाप्रबंधक (विपणन), शुभा बंछोर, उप प्रबंधक (विपणन), शैलेश दुबे, तथा उप महाप्रबंधक (सी एंड आईटी), चंद्रकली साहू एवं दीपमाला का प्रत्यक्ष एवं महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस अवसर पर शुभा बंछोर ने डिजिटल साइनिंग मॉड्यूल की कार्यप्रणाली एवं इसके प्रमुख लाभों पर एक संक्षिप्त प्रस्तुति भी दी।

यह पहल भिलाई इस्पात संयंत्र में पेपर-लेस कार्यप्रणाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके माध्यम से डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित एवं छेड़छाड़-रहित दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सीधे ग्राहकों एवं एमजंक्शन के साथ साझा किया जा सकेगा। इससे न केवल दस्तावेजों के आदान-प्रदान की प्रक्रिया अधिक त्वरित एवं सुविधाजनक होगी, बल्कि मैनुअल प्रक्रिया पर निर्भरता कम करते हुए कार्यक्षमता में भी वृद्धि होगी।

डिफॉल्टरों की जमा राशि होगी जब्त

भिलाई। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के मोर मकान मोर आस घटक के अंतर्गत किरायेदारी के रूप में निवासरत् किरायेदारों व बेघर परिवारों से शासन द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र के साथ पात्रता संबंधी संपूर्ण दस्तावेज जमा कराकर सक्षम स्वीकृति पश्चात् शासन के दिशा निर्देशानुसार कुल अंशदान राशि का 10 प्रतिशत राशि जमा कराकर विधिवत पूर्ण पारदर्शिता से आवासों का आबंटन किया गया है। आवास आबंटन होने के 01 माह उपरान्त से लेकर लगातार 09 माह तक 10 प्रतिशत के समान किश्तों की राशि को निगम कोष में जमा करना अनिवार्य होगा। जिसके संबंध में आबंटिती को लॉटरी द्वारा आवास आबंटन हेतु जारी सूचना पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है, तथा शासन से जारी दिशा निर्देश में उल्लेख है, कि हितग्राही द्वारा प्रदाय चेक लगातार 02 बार बाउन्स होते है / समयावधि में राशि प्रदाय नही की जाती है, तो हितग्राही को डिफाल्टर घोषित करते हुए हितग्राही द्वारा भुगतान की गयी प्रथम एवं द्वितीय किश्त की राशि राजसात की जावेगी।卐 जो हितग्राही आबंटन माह से 09 तक अपना पूर्ण बकाया अंशदान राशि निगम कोष में जमा नही किये हैं उनका आबंटन निरस्त किया जावेगा। इस विज्ञप्ति प्रकाशन को आम सूचना मान कर प्रकाशन किया जा रहा है।

Since 1972
CROWN-TV
Choice Of Millions
LED / Washing Machine
Cooler / Fridge
Available All Size

CONTACT :
Atlas Radio Traders (Crown)
Sect.-3, D-48, Ward No. 13
Devendra Nagar, Raipur (C.G.) 492009
Near Akash Gas Agency Line
Mob.: 98262 52372

नक्सलवाद के अंधेरे से निकलकर विकास की नई इबारत लिख रहा छत्तीसगढ़ : मुख्यमंत्री साय

बस्तर में पर्यटन, रोजगार और आजीविका के खुल रहे नए द्वार

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि दशकों तक नक्सलवाद की चुनौती का सामना करने वाला छत्तीसगढ़ आज शांति, विश्वास और विकास के एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है। नक्सलवाद के अंधेरे से बाहर निकलकर प्रदेश अब विकास की नई इबारत लिख रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, अधोसंरचना, पर्यटन और आजीविका सहित सर्वांगीण विकास के प्रत्येक क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है और इसके सकारात्मक परिणाम धरातल पर दिखाई देने लगे हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय राजधानी रायपुर में टाइम्स नाउ नवभारत डॉट कॉम द्वारा आयोजित 'विकसित भारत-समृद्ध छत्तीसगढ़ : विकास का नया अध्याय' कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प देश के सामने रखा है। इसी संकल्प के अनुरूप छत्तीसगढ़ ने भी विकसित राज्य बनने का स्पष्ट रोडमैप तैयार किया है। प्रदेश के विजन डॉक्यूमेंट के अंतर्गत 10 प्रमुख मिशन निर्धारित किए गए हैं और उन्हें धरातल पर उतारने के लिए लगातार काम किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ संभावनाओं से भरपूर राज्य है। प्रदेश का लगभग 44 प्रतिशत भू-भाग वनों से आच्छादित है और यहां लोहा, बॉक्साइट, लिथियम, सोना सहित अनेक महत्वपूर्ण खनिज संसाधन उपलब्ध हैं। छत्तीसगढ़ देश का एकमात्र टिन उत्पादक राज्य भी है। प्राकृतिक संसाधनों की इस समृद्धि के साथ प्रदेश की मेहनतकश मानव शक्ति हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इन क्षमताओं का समुचित उपयोग कर छत्तीसगढ़ आने वाले वर्षों में देश के विकास में और बड़ी भूमिका निभाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर की जनता ने लगभग चार दशकों तक नक्सल हिंसा का दंश झेला है। नक्सली स्कूल, अस्पताल, सड़क, पुल-पुलिया और संचार सुविधाओं जैसे विकास कार्यों का विरोध करते थे, जिसके कारण अनेक दूरस्थ क्षेत्र विकास की मुख्यधारा से कटे रहे। इसलिए सरकार ने नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक लड़ाई के साथ-साथ विकास को भी समान प्राथमिकता दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने बस्तर को देश का सबसे सुंदर आदिवासी संभाग बनाने का संकल्प व्यक्त किया है और राज्य सरकार इसी लक्ष्य के अनुरूप बस्तर के समग्र विकास पर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान के अंतर्गत 34 लाख लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है और लगभग 40 हजार लोगों का उपचार किया गया है। 'बस्तर मुन्ने' कार्यक्रम के माध्यम से शासकीय अमला गांवों में पहुंचकर और वहां ठहरकर लोगों को योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ उपलब्ध करा रहा है।

हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में लौटने वालों के लिए खोले पुनर्वास के द्वार

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सरकार की रणनीति केवल सुरक्षा कार्रवाई तक सीमित नहीं रही। हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटने वाले लोगों के लिए बेहतर आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति तैयार की गई। सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया कि हिंसा छोड़कर लौटने वालों के साथ न्याय होगा और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिलेगा।

उन्होंने कहा कि सरकार ने हिंसा की जगह संवाद और पुनर्वास को प्राथमिकता दी, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए और बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा का रास्ता चुना।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सशस्त्र नक्सलवाद समाप्त होने के बाद भी वैचारिक स्तर पर भ्रम फैलाने की कोशिश करने वाले कुछ तत्व मौजूद हैं, लेकिन बस्तर में तेजी से पहुंचता विकास और लोगों के जीवन में आ रहा सकारात्मक परिवर्तन ऐसे भ्रम का सबसे प्रभावी उत्तर है।

युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए शिक्षा और रोजगार पर विशेष जोर

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। राज्य निर्माण के समय प्रदेश में केवल एक मेडिकल कॉलेज था, जबकि आज 15 मेडिकल कॉलेज संचालित हैं। प्रत्येक विकासखंड तक उच्च शिक्षा की पहुंच बढ़ी है और आईआईटी, आईआईएम, ट्रिपल आईटी जैसे राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित संस्थान प्रदेश में संचालित हो रहे हैं।

उन्होंने बताया कि प्रदेश के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी बेहतर वातावरण उपलब्ध कराया जा रहा है। दिल्ली में यूथ हॉस्टल के माध्यम से युवाओं को यूपीएससी की तैयारी में सहयोग दिया जा रहा है। प्रदेश में 34 नालंदा परिसरों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे विद्यार्थियों को अध्ययन और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिक परिवारों के बच्चों की शिक्षा और उनके बेहतर भविष्य के लिए भी सरकार अनेक सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। सरकार का प्रयास है कि आर्थिक परिस्थितियां किसी प्रतिभाशाली बच्चे के सपनों की राह में बाधा न बनें।

नई औद्योगिक नीति से निवेश और रोजगार को मिल रही नई गति

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि नई औद्योगिक नीति के माध्यम से छत्तीसगढ़ में उद्योग, निवेश और रोजगार के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया गया है। अब तक लगभग 8 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और इनका असर धरातल पर भी दिखाई देने लगा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता केवल निवेश आकर्षित करना नहीं है, बल्कि उसके माध्यम से प्रदेश के युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर तैयार करना है। इसी उद्देश्य से एक हजार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने वाले उद्यमों के लिए विशेष प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। बड़ी संख्या में युवाओं को कौशल विकास से जोड़ा गया है।

शांति के साथ बढ़ी आजीविका और पर्यटन की संभावनाएं

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बस्तर में शांति स्थापित होने के साथ अब रोजगार, आजीविका और पर्यटन के नए अवसर भी तेजी से विकसित हो रहे हैं। पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के साथ समझौता किया गया है। बकरी पालन और मत्स्य पालन जैसी गतिविधियों के माध्यम से स्थानीय लोगों की आय बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि बस्तर की प्राकृतिक सुंदरता, जनजातीय संस्कृति और जीवनशैली पूरी दुनिया को आकर्षित कर रही है। बस्तर के धुड़मारास गांव को दुनिया के श्रेष्ठ पर्यटन गांवों में शामिल किया गया है। यहां आने वाले देश-विदेश के पर्यटक होम-स्टे में रहकर स्थानीय जनजातीय जीवन और संस्कृति को निकट से अनुभव कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर में होम-स्टे को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ऋण एवं अनुदान की सुविधा दे रही है। पर्यटन को रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था से जोड़ने के उद्देश्य से नई औद्योगिक नीति में पर्यटन को भी शामिल किया गया है। नक्सलवाद की समाप्ति के बाद खाली हो रहे लगभग 70 सुरक्षा कैंपों को 'सेवा डेरा' के रूप में विकसित करने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है।

सुरक्षा और विकास की समन्वित रणनीति से बदली बस्तर के वनांचलों की तस्वीर

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि लंबे समय तक नक्सलवाद प्रदेश, विशेषकर बस्तर के विकास में सबसे बड़ी बाधा बना रहा। वर्ष 2023 में राज्य में सरकार बनने के बाद जनवरी 2024 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की स्थिति की समीक्षा की। इसके बाद केंद्र और राज्य सरकार ने समन्वय के साथ नई रणनीति पर काम शुरू किया।

पड़ोसी राज्यों के साथ बेहतर तालमेल और सुरक्षा बलों की संयुक्त कार्रवाई ने नक्सलवाद के विरुद्ध अभियान को निर्णायक गति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की दृढ़ इच्छाशक्ति और हमारे सुरक्षा बलों के अदम्य साहस से सशस्त्र नक्सलवाद के खिलाफ ऐतिहासिक सफलता मिली है।

नई रणनीति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही कि सुरक्षा बलों ने पूरी मजबूती से अभियान चलाते हुए पहले की तुलना में अपने जवानों की क्षति को कम रखा।

किसान परिवार से मिली मेहनत और जिम्मेदारी की सीख

कार्यक्रम में अपनी जीवनयात्रा का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि वे किसान परिवार से आते हैं और खेती उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा रही है। दस वर्ष की आयु में पिता के निधन के बाद परिवार के बड़े बेटे के रूप में कम उम्र में ही उन्हें जिम्मेदारियां संभालनी पड़ीं। बचपन से खेती करते हुए उन्होंने परिश्रम, धैर्य और जिम्मेदारी का महत्व सीखा।

उन्होंने कहा कि राजनीति में आने की उनकी कोई पूर्व योजना नहीं थी। गांव के लोगों के आग्रह पर पहली बार वार्ड पंच का चुनाव लड़ा और जनप्रतिनिधि के रूप में सार्वजनिक जीवन की शुरुआत हुई। पांच वर्ष तक पंच के रूप में किए गए कार्यों के आधार पर गांववासियों ने उन्हें निर्विरोध सरपंच चुना। इसके बाद वर्ष 1990 में तपकरा विधानसभा क्षेत्र से पहली बार विधायक बने। अविभाजित मध्यप्रदेश में दो बार विधायक और रायगढ़ से चार बार सांसद के रूप में जनता की सेवा का अवसर मिला। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में केंद्रीय राज्यमंत्री के रूप में कार्य करने का अवसर मिला और आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश की सेवा का महत्वपूर्ण दायित्व मिला है। सार्वजनिक जीवन में जो भी जिम्मेदारी मिली, उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाने का प्रयास किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ के सामने संभावनाओं का नया आकाश है। नक्सलवाद की बाधा दूर होने के साथ बस्तर सहित पूरा प्रदेश विकास की नई गति पकड़ रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध छत्तीसगढ़ मानव विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्योग और पर्यटन में भी देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो तथा वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' के निर्माण में 'विकसित छत्तीसगढ़' अपनी सशक्त भूमिका निभाए।

'नियद नेल्लानार' ने दूरस्थ गांवों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सरकार शुरू से स्पष्ट थी कि केवल नक्सल समस्या को समाप्त करना पर्याप्त नहीं होगा। स्थायी शांति के लिए बस्तर के प्रत्येक गांव और प्रत्येक परिवार तक विकास का लाभ पहुंचाना आवश्यक है। इसी सोच के साथ 'नियद नेल्लानार' योजना शुरू की गई। गोंडी भाषा में इसका अर्थ है - 'आपका अच्छा गांव'। उन्होंने बताया कि इस योजना के माध्यम से दूरस्थ और संवेदनशील गांवों में सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और दूरसंचार जैसी बुनियादी सुविधाएं तेजी से पहुंचाई जा रही हैं। क्षेत्र में 421 से अधिक स्कूल खोले गए हैं और दूरसंचार नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है। विकास को और गति देने के लिए सरकार ने 'नियद नेल्लानार 2.0' भी प्रारंभ किया है।

अवंतीबाई लोधी, मिनी माता एवं बहादुर कलारिन सम्मान के लिए 25 सितम्बर से पहले करें आवेदन

श्रीकंचनपथ समाचार

अम्बिकापुर। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महिलाओं, विशेष कर वीरता, शौर्य, साहस तथा महिलाओं में आत्मबल को सशक्त करने के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली राज्य की महिलाओं को प्रतिवर्ष 'वीरांगना' रानी अवंतीबाई लोधी स्मृति पुरस्कार प्रदान किया जाना है। शासन द्वारा महिलाओं, विशेष रूप से अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक महिलाओं के उत्थान हेतु उत्कृष्ट कार्य करने वाली राज्य की एक महिला/अशासकीय संस्था को प्रतिवर्ष 'मिनी माता सम्मान (महिला उत्थान)' प्रदान किया जाना है। इसी प्रकार महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष, नारी उत्थान हेतु अभूतपूर्व

कार्य करने वाली राज्य की महिला को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से प्रतिवर्ष ''माता बहादुर कलारिन सम्मान'' प्रदान किया जाना है। इसके तहत एक महिला को दो लाख रूपए की राशि तथा प्रशस्ति पट्टिका सम्मान के रूप में प्रदान किए जाने का प्रावधान है। इन पुरस्कारों हेतु प्रविष्टियां 25 सितम्बर 2026 तक जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग को प्रस्तुत किया जा सकता है। विस्तृत जानकारी जिला कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग से प्राप्त की जा सकती है।

आज की छोटी बचत-कल की ताकत : महतारी वंदन के सहारे सुकृति के सुनहरे कल की नींव

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। जब इरादे नेक हों और सोच दूरदर्शी, तो सरकारी सहायता योजनाएं केवल जीवनयापन का साधन नहीं बनतीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी की तकदीर बदलने का जरिया बन जाती हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना का ऐसा ही एक प्रेरणादायक और अनुकरणीय उदाहरण बस्तर अंचल के नारायणपुर जिले में देखने को मिल रहा है।

नारायणपुर नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 8 की निवासी श्रीमती जय ललिता कश्यप ने अपनी 5 वर्षीय लाडली बेटी सुकृति कश्यप के भविष्य को आर्थिक सुरक्षा देने की एक अनूठी और सराहनीय मिसाल

कायम की है।

अप्रैल 2024 से महतारी वंदन योजना के तहत हर महीने मिलने वाली वित्तीय सहायता को दैनिक खर्चों में उड़ाने के बजाय, जय ललिता और उनके पति गजेंद्र कश्यप ने एक दूरगामी निर्णय लिया। उन्होंने इस राशि का सीधा रुख अपनी बेटी के सुखद भविष्य की ओर मोड़ दिया।

जय ललिता ने महतारी वंदन योजना से प्राप्त राशि से पोस्ट ऑफिस में बेटी सुकृति के नाम से सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाया और उसमें नियमित रूप से मासिक बचत जमा करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि बेटी के भविष्य को सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाना हर माता-पिता का सपना होता है। आज की यह छोटी-छोटी बचत कल सुकृति के सपनों को पूरा करने में बहुत बड़ी मददगार साबित होगी।

सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार की एक ऐसी बचत योजना है जो बालिकाओं की शिक्षा, उच्च अध्ययन और शादी के लिए एक निश्चित और सुरक्षित फंड तैयार करती है।

सोफे पर बैठकर मैं खुद को एक्सपर्ट समझने लगी थी

KKK 15 से बाहर होने के बाद अविका गोर का इमोशनल पोस्ट

टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस अविका गोर इन दिनों 'खतरों के खिलाड़ी 15' से अपने एलिमिनेशन के बाद चर्चा में हैं। शो से बाहर होने कुछ दिनों बाद एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर एक लंबा नोट शेयर किया, जिसमें उन्होंने रियलिटी शो के अनुभव, अपनी परफॉर्मेंस और एलिमिनेशन के बाद मन में चल रहे सवालों को बेहद ईमानदारी से बयां किया।

अविका ने बताया कि शो के नए एपिसोड देखने के दौरान उन्हें खुद के बारे में एक दिलचस्प बात महसूस हुई। उन्हें लगता था कि अगर वह उस समय वहां होतीं तो ज्यादा बेहतर परफॉर्म करतीं, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि टीवी स्क्रीन के सामने बैठकर किसी स्टंट को जज करना और उसे असल में करना बिल्कुल अलग अनुभव है।

बाहर बैठकर हर कोई खुद को हीरो समझ सकता है

अविका ने लिखा कि शो देखने के दौरान उनके मन में कई बार आया कि अगर वह वहां होतीं तो हार नहीं मानतीं और ज्यादा मेहनत करतीं। लेकिन अगले ही पल उन्हें एहसास हुआ कि वह अपने आरामदायक सोफे पर बैठकर सब कुछ देख रही हैं।

उनके मुताबिक, उन्हें पहले से पता है कि स्टंट में आगे क्या होने वाला है, जबकि प्रतियोगी के सामने उस वक्त डर, दबाव और एड्रेनालिन के बीच चुनौती खड़ी होती है। ऐसे में किसी परिस्थिति से बाहर रहकर खुद को उसका हीरो समझना आसान होता है।

लगता है मेरे अंदर अभी बहुत कुछ बाकी था

अविका ने माना कि इतनी जल्दी एलिमिनेट होना उनके लिए पूरी तरह स्वीकार कर पाना आसान नहीं रहा। उनके अंदर अब भी यह भावना है कि वह शो में और बेहतर कर सकती थीं। उन्होंने लिखा कि जब कोई चीज हमारे लिए बहुत मायने रखती है तो हम बार-बार सोचते हैं कि अगर उस वक्त कोई दूसरा फैसला लिया होता तो क्या होता। यही सोच कई बार हमें ऐसी कहानी की कल्पना करने पर मजबूर करती है, जो असल में कभी हुई ही नहीं।

21 साल की उम्र में पहली बार पहुंची थीं शो में

यह पहली बार नहीं है जब अविका ने 'Khatron Ke Khiladi' में हिस्सा लिया। वह इससे पहले शो के नौवें सीजन का भी हिस्सा रह चुकी हैं। एक्ट्रेस ने बताया कि जब वह पहली बार शो में आई थीं, तब उनकी उम्र सिर्फ21 साल थी।

उस अनुभव ने उन्हें अपनी पहचान और भविष्य को नए नजरिए से देखने में मदद की थी। इस बार शो में वापसी उनके लिए इसलिए भी खास थी क्योंकि उन्हें लगा कि शायद वह अपने पुराने रूप से दोबारा मिलना चाहती हैं और अधूरे अनुभव को पूरा करना चाहती हैं।

इस बार सीखा - जो कंट्रोल में नहीं, उसे स्वीकार करना

अविका के मुताबिक, पहली बार शो ने उन्हें यह समझने में मदद की कि वह कौन हैं और क्या बनना चाहती हैं। लेकिन इस बार 'Khatron Ke Khiladi' ने उन्हें एक अलग सबक दिया है—हर चीज का अंत अपनी इच्छा के मुताबिक बदलना संभव नहीं होता।

उन्होंने कहा कि अब वह अपने एलिमिनेशन की कहानी को बार-बार बदलने के बजाय उसे स्वीकार करना सीख रही हैं। उनका मानना है कि यह सोचने की जरूरत नहीं कि उनके पास और बेहतर करने की क्षमता थी या नहीं, बल्कि उन्होंने जो किया, उसकी भी कद्र करनी चाहिए।

Orry से मुकाबले में हुईं एलिमिनेट

अविका का एलिमिनेशन Orry के साथ हुए एलिमिनेशन राउंड के बाद हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक, Orry ने स्टंट करीब 10 मिनट में पूरा किया, जबकि अविका को इसे पूरा करने में 13 मिनट से ज्यादा समय लगा। रोहित शेट्टी के होस्ट किए जाने वाले इस सीजन में रुबीना दिलैक, ऋत्विक धनजानी, फरहान भट्ट, करण वाही समेत कई चर्चित सितारे बतौर कंटेस्टेंट नजर आ रहे हैं।

एक-दूसरे के आमने-सामने आए करीना पृथ्वीराज, 'दायरा' का ट्रेलर रिलीज

करीना कपूर ने खाकी वर्दी पहनी है। अपराध का एक मामला है। जांच जारी है। खाकी में ही पृथ्वीराज सुकुमारन नजर आए हैं। अपराध का वही मामला उनके भी सामने है और जांच जारी है। मगर, दोनों एक-दूसरे के आमने-सामने हैं। एक ही विभाग और मामले की जांच का एक ही लक्ष्य। फिल्म में करीना कपूर को डीसीपी अजूनी कोहली की भूमिका में देखा जाएगा। वहीं, पृथ्वीराज को डीसीपी रमन कुमार के रूप में।

कैसा है 'दायरा' का ट्रेलर?

मेघना गुलजार निर्देशित फिल्म 'दायारा' का ट्रेलर 31 अगस्त को रिलीज हुआ है। ट्रेलर की शुरुआत में एक अपराधी को पुलिस वैन में अंधेरे इलाके में ले जाया जाता है। वह पूछता है, 'इधर क्यों लाए हैं सब'? पृथ्वीराज सुकुमारन की आवाज आती है, 'बताता हूं'। अगले ही सीन में पृथ्वीराज सुकुमारन प्रेस कांफ्रेंस में अपराधी के एनकाउंटर की वजह बताते हैं कि आरोपी ने मौका ढूंढते ही भागने की कोशिश की। हमारी टीम पर अटैक किया। पुलिस ने सेल्फडिफेंस में मार दिया।

करीना कपूर ने शुरू से की जांच

सवाल उठता है कि क्या यह एक योजनाबद्ध पुलिस एनकाउंटर था आगे करीना कपूर पीड़ित परिवार के पास जाती हैं और घटना के बारे में शुरू से पूछती हैं कि 07 अक्टूबर को क्या हुआ था? पता चलता है कि एक मां अपनी गुमशुदा बेटी की सूचना देने थाने गई और एफआईआर दर्ज कराई। जांच के दौरान मालूम हुआ के गुमशुदा बच्ची का यौन शोषण हुआ। आरोपी नाबालिग है।

कब रिलीज होगी 'दायरा'?

क्राइम सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है, जिसे पेन स्टूडियोज और जंगली पिक्चर्स के बैनर तले प्रोड्यूस किया गया है। यह फिल्म 18 सितंबर को रिलीज होने वाली है।

न शक हुआ, न पकड़ी गईं...

क्रिस्टल डिसूजा की इस रणनीति ने पहुंचाया फिनाले तक, करण जौहर भी हुए फैन

रियलिटी शो 'द ट्रेटर्स सीजन 2' में क्रिस्टल डिसूजा ने अपनी रणनीति के दम पर फिनाले में जगह बना ली है। शो के होस्ट करण जौहर ने भी उनके गेमप्ले और दबाव के बीच संयम बनाए रखने की तारीफ की है। शो में 'ट्रेटर' की भूमिका निभा रहीं क्रिस्टल ने शुरुआत से ही बेहद सावधानी से गेम खेला। उन्होंने हर बातचीत में सक्रिय रूप से शामिल होने के बजाय यह समझने पर ध्यान दिया कि कंटेस्टेंट्स का शक किस ओर जा रहा है। जरूरत पड़ने पर ही उन्होंने हस्तक्षेप किया, जिससे वह लंबे समय तक शक के घेरे से बाहर रहीं।

करीबी दोस्त रिया चक्रवर्ती पर घूमी 'सर्कल ऑफ शैक'

हालिया एपिसोड में करण जौहर ने क्रिस्टल की रणनीति की तारीफ करते हुए कहा कि आपने बहुत ही समझदारी से गेम खेला है। उन्होंने यह भी बताया कि क्रिस्टल ने मुश्किल परिस्थितियों में खुद पर नियंत्रण बनाए रखा और सोच-समझकर फैसले लिए।

'सर्कल ऑफ शैक' के दौरान शक की सुई क्रिस्टल की करीबी दोस्त रिया चक्रवर्ती की ओर घूम गई। क्रिस्टल ने इस स्थिति का फायदा उठाया और रिया पर ही शक बने रहने दिया। इससे वह खुद को संदेह से दूर रखने में कामयाब रहीं।

क्रिस्टल की स्थिति और मजबूत हो गई

वहीं, साथी 'ट्रेटर' शाहनील गिल के गेम से बाहर होने के बाद क्रिस्टल की स्थिति और मजबूत हो गई। अकेली बची ट्रेटर के तौर पर उन्हें अपनी टीम में एक और कंटेस्टेंट को शामिल करने का मौका मिला। उन्होंने रिडा थराना को चुना, जो पहले ही ट्रेटर्स की पहचान जानने की इच्छा जाहिर कर चुकी थीं।

क्रिस्टल डिसूजा और रिडा थराना के अलावा मल्लिका शेरावत और शालिनी पासी समेत कुल छह कंटेस्टेंट्स ने 'द ट्रेटर्स सीजन 2' के फिनाले में जगह बनाई है। क्रिस्टल की शांत और रणनीतिक गेमप्ले ने उन्हें शो के सबसे मजबूत खिलाड़ियों में शामिल कर दिया है।

साउथ की एक जानी-मानी एक्ट्रेस श्रिया रेड्डी? फिल्म महाकाली में अक्षय खन्ना संग मचाएंगी धमाल

बॉलीवुड एक्टर अक्षय खन्ना की अपकमिंग फिल्म महाकाली की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। फिल्म का टीजर रिलीज हो चुका है। फिल्म में अक्षय खन्ना असुरगुरु शुक्राचार्य का रोल प्ले करते नजर आएंगे। वहीं दूसरी तरफ एक्ट्रेस श्रिया रेड्डी महाकाली के रूप में नजर आएंगी। टीजर रिलीज होने के बाद से वो काफी सुर्खियां बटोर रही हैं. ऐसे में चलिए जानते हैं वो कौन हैं।

बता दें, श्रिया रेड्डी साउथ की एक जानी-मानी एक्ट्रेस हैं। वो एक्स इंडियन टेस्ट क्रिकेटर भरत रेड्डी की बेटी हैं। श्रिया रेड्डी ने अपने करियर की शुरुआत एस एस म्युजिक में एक वीडियो जॉकी के रूप में की थी। इसके बाद उन्होंने मॉडलिंग और अभिनय की दुनिया में कदम रखा।

श्रिया रेड्डी ने साल 2002 में तमिल फिल्म समुराई से अपने अभिनय सफर की शुरुआत की थी। उन्होंने ब्लैक, थिमिरु, कांचीवरम और प्रभास की ब्लॉकबस्टर फिल्म सालार जैसी पॉपुलर फिल्मों में काम किया है। सालार ने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की थी।

पर्सनल लाइफ की बात करें तो श्रिया रेड्डी ने 9 मार्च साल 2008 में विक्रम कृष्णा से शादी की है, जो की खुद एक एक्टर हैं। उनकी एक बेटी भी है। श्रिया रेड्डी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 2.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं।

अब श्रिया रेड्डी महाकाली में धमाल मचाती नजर आने वाली हैं। फिल्म का टीजर हाल ही में रिलीज कर दिया गया है। टीजर में एक्ट्रेस महाकाली के दमदार किरदार में दिखीं। वो गोद में एक छोटे बच्चे को सुलाती नजर आईं।

इस फिल्म को पूजा अपर्णा कोल्लुरु डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म महाकाली अगले साल 8 जनवरी 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

एक ही समय पर दस्त और कब्ज लगने के हो सकते हैं ये 5 कारण

दस्त और कब्ज, दोनों ही पेट की समस्याएं हैं, जो अलग-अलग लक्षण और इलाज रखती हैं। हालांकि, कुछ स्थितियों में ये दोनों समस्याएं एक साथ हो सकती हैं। इस लेख में हम उन 5 कारणों के बारे में जानेंगे, जिनसे एक ही समय पर दस्त और कब्ज, दोनों लग सकते हैं। इन कारणों को जानकर आप बेहतर तरीके से इन समस्याओं का इलाज कर सकते हैं और अपनी सेहत को सुधार सकते हैं।

खाने में बदलाव

खाने में अचानक बदलाव करने से पाचन तंत्र प्रभावित हो सकता है। अगर आप अचानक से ज्यादा फाइबर वाला या गलत खाने का सेवन करने लगते हैं तो इससे दस्त और कब्ज, दोनों हो सकते हैं।

इसके अलावा ताजे फल और सब्जियों की कमी भी इस समस्या का कारण बन सकती है। इसलिए, अपने खाने में धीरे-धीरे बदलाव करें और ऐसा खाना खाएं, जिसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर की सही मात्रा हो।

पानी की कमी

शरीर में पानी की कमी भी दस्त और कब्ज, दोनों का कारण बन सकती है।

जब शरीर को पर्याप्त पानी नहीं मिलता तो यह अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए मल को अधिक अवशोषित कर लेता है, जिससे कब्ज हो जाते है।

वहीं, कुछ मामलों में यह पेट के बैक्टीरिया को असंतुलित कर देती है, जिससे दस्त लग जाते हैं। इसलिए, रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी है।

संक्रमण या बीमारी

कुछ संक्रमण या बीमारियां भी दस्त और कब्ज, दोनों का कारण बन सकती हैं। जैसे आंतों की सूजन, फ्लू वायरस या बैक्टीरियल संक्रमण।

इन मामलों में डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी होता है, ताकि सही इलाज मिल सके और समस्या का समाधान भी हो सके। इसके अलावा पेट के संक्रमण के कारण भी दस्त और कब्ज, दोनों लग सकते हैं।

ऐसे में डॉक्टर से संपर्क करना बेहद जरूरी होता है।

मानसिक तनाव

मानसिक तनाव, जैसे चिंता या तनाव भी पाचन तंत्र पर बुरा असर डाल सकता है, जिससे दस्त और कब्ज लग सकते हैं। जब शरीर में तनाव होता है तो यह पेट पर दबाव डालता है, जिससे मल सख्त हो जाता है या तरल हो जाता है।

इसलिए, मानसिक शांति बनाए रखना बहुत जरूरी है, ताकि पेट स्वस्थ रहे और ऐसी समस्याएं न हों। इसके लिए नियमित ध्यान या योग करना फायदेमंद हो सकता है।

दवाइयों का असर

कुछ दवाइयों के सेवन से भी दस्त या कब्ज जैसी समस्याएं हो सकती हैं। खासकर अगर आप किसी संक्रमण या बीमारी का इलाज करवा रहे हों तो डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाइयों का ही सेवन करें।

गलत दवाइयों के सेवन से शरीर पर बुरा असर पड़ता है, जिससे पेट संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

इन कारणों को जानकर आप बेहतर तरीके से इन समस्याओं का इलाज कर सकते हैं और अपनी सेहत को सुधार सकते हैं।

अक्षय ओबेरॉय की फिल्म लव लॉटरी का पहला लुक जारी

एक्टर अक्षय ओबेरॉय और हेली दारूवाला स्टारर और सच्ची घटनाओं से प्रेरित फिल्म लव लॉटरी का फर्स्ट लुक रिलीज हो गया है। महज 49 सेकंड का यह वीडियो अपने रहस्यमयी अंदाज, दमदार विजुअल्स और सस्पेंस से भरपूर बैकग्राउंड स्कोर के साथ दर्शकों की उत्सुकता बढ़ा रहा है। फिल्म कोर्टरूम ड्रामा, मर्डर मिस्ट्री और सस्पेंस थ्रिलर का दिलचस्प मिश्रण है, जिसमें रिश्तों, कानून और समाज के कई संवेदनशील पहलुओं को कहानी का हिस्सा बनाया गया है।

फर्स्ट लुक में कहानी का ज़्यादा खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन फिल्म के प्रमुख किरदारों की झलक दर्शकों की उत्सुकता बढ़ाने के लिए काफी है। इसमें अक्षय ओबेरॉय, हेली दरूवाला, कबीर दुहान सिंह, हेमंत पांडे, विजयंत कोहली और अग्नि अग्यारी अपने अलग-अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। वहीं वीडियो के आखिर में संतोष शुक्ला की एंट्री कहानी के रहस्य को और गहरा कर देती है।

फिल्म में अक्षय ओबेरॉय और हेली दरूवाला के अलावा कबीर दुहान सिंह, विजयंत कोहली, हेमंत पांडे, इंदिरा कृष्णन, संतोष शुक्ला, विक्रम शर्मा, अग्नि अग्यारी, कुमार सौरभ, अश्वंत लोढ़ी और अर्शदीप संधू अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे। 18 सितंबर 2026 को रिलीज होने वाली लव लॉटरी एक ऐसे आधुनिक शहरी कपल की कहानी है, जिनकी शादीशुदा ज़िंदगी में आई दरार धीरे-धीरे एक जटिल कानूनी लड़ाई में बदल जाती है। इसी बीच एक मर्डर मिस्ट्री, कई चौंकाने वाले खुलासे कहानी को नए मोड़ देती हैं।

फिल्म रिश्तों में विश्वास, सामाजिक धारणा, भावनात्मक शोषण और गंभीर आरोपों के मनोवैज्ञानिक प्रभाव जैसे विषयों को भी छूती है। फिल्म की शूटिंग उत्तराखंड की खूबसूरत लोकेशंस पर की गई है। प्राकृतिक वादियों और मनमोहक दृश्यों को कहानी का अहम हिस्सा बनाया गया है, जिससे फिल्म का विजुअल एक्सपीरियंस और भी शानदार बन गया है।

फिल्म के निर्माता कुलदीपदरूवाला उर्फ तुषार ने कहा, हम चाहते थे कि लव लॉटरी सिर्फ एक मनोरंजक फिल्म न बने, बल्कि दर्शकों को सोचने पर भी मजबूर करे। इसमें सस्पेंस, इमोशंस और सामाजिक रूप से प्रासंगिक विषयों का ऐसा मेल देखने को मिलेगा जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखेगा।

खास-खबर

रायपुर के नंदनवन का 50 करोड़ से होगा कायाकल्प

रायपुर। रायपुर जिले के अटारी गांव स्थित नंदनवन को अब एक नए और आकर्षक स्वरूप में पुनर्विकसित किया जाएगा। मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक के दौरान वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिकारियों ने मुख्य सचिव विकासशील के समक्ष नंदनवन पुनर्विकास की प्रस्तावित परियोजना का प्रस्तुतिकरण दिया। नंदनवन के कायाकल्प और विकास कार्य में लगभग 50 करोड़ रुपये का निवेश अनुमानित है। पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत यह पूरी परियोजना पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित होगी। बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए बॉटनिकल गार्डन को नए सिरे से पुनर्जीवित और विकसित किया जाएगा। मुख्य सचिव ने परियोजना में पर्यटकों की सुविधा और आकर्षण को ध्यान में रखते हुए विभिन्न जन-सुविधाएं विकसित करने के कड़े निर्देश दिए हैं।

जशपुर में बनेगा फुटबाल स्टेडियम, राज्य शासन ने मंजूर किए 5.49 करोड़

रायपुर। राज्य शासन ने जशपुर में फुटबॉल स्टेडियम के निर्माण के लिए 5 करोड़ 49 लाख 40 हजार रुपए मंजूर किए हैं। उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने आज मंत्रालय से इसकी प्रशासकीय स्वीकृति के आदेश जारी कर दिए हैं। जशपुर के झरगांव में करीब चार एकड़ में इस स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। फुटबॉल मैदान के साथ ही यहां स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स व गैलरी, मिनी स्टेज, पार्किंग, पैवेलियन, खिलाड़ियों और दर्शकों के लिए पृथक-पृथक टॉयलेट भी बनाए जाएंगे। इस सर्वसुविधायुक्त फुटबॉल स्टेडियम के निर्माण से क्षेत्र के खिलाड़ियों को आधुनिक खेल सुविधाएं मुहैया होंगी।

किसानों की सुविधा के लिए सुकमा जिले में बढ़े धान उपार्जन केन्द्र

सुकमा। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में जिले के किसानों को धान बेचने के लिए बेहतर और सुगम सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण पहल की है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में जिले में संचालित 25 धान उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से धान की खरीदी की गई थी। किसानों की सुविधा और दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक उपार्जन व्यवस्था की पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के आदेशानुसार विकासखंड सुकमा के बडेसट्टी एवं बुडदी में 02 नवीन धान उपार्जन केन्द्र स्वीकृत किए गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में किसानों के हितों को प्राथमिकता देते हुए लिए गए इस निर्णय से अब सुकमा जिले में कुल 27 धान उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से धान की खरीदी की जाएगी।

कांकेर पहुंचे योग आयोग के अध्यक्ष संजय अग्रवाल

जन-जन तक योग को पहुंचाने की पहल

भानुप्रतापुर में परिचर्चा व संवाद

श्रीकंचनपथ न्यूज

कांकेर। छत्तीसगढ़ में योग को जन-जन और प्रदेश के कोने-कोने तक पहुंचाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ योग आयोग, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के अध्यक्ष संजय अग्रवाल का प्रवास दौरा प्रारंभ हो गया है। प्रवास के प्रथम चरण में जिला कांकेर के भानुप्रतापपुर क्षेत्र अंतर्गत हाटकर्रा एवं कोरर ग्राम में योग विषय पर परिचर्चा, बैठक एवं जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में गायत्री परिवार के सदस्यों, ग्रामवासियों तथा स्कूली छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए योग आयोग के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने कहा कि समाज और देश में सकारात्मक परिवर्तन की शुरुआत स्वयं से करनी होगी। उन्होंने कहा कि अगर हम बदलेंगे, तो देश बदलेगा।

क्रोध, पश्चाताप और मानसिक तनाव जैसी स्थितियां मनुष्य के भीतर ही उत्पन्न होती हैं और योग के माध्यम से व्यक्ति अपने मन, विचार एवं जीवनशैली में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। अग्रवाल ने कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवन, अनुशासन और सकारात्मक सोच का माध्यम है। उन्होंने उपस्थित लोगों से स्वास्थ्य को लेकर संकल्प लेने तथा योग को अपनी दैनिक जीवनशैली का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों, गायत्री परिवार के सदस्यों एवं विद्यार्थियों ने योग, स्वास्थ्य, नशामुक्ति और स्वस्थ जीवनशैली से जुड़े विषयों पर चर्चा की। संजय अग्रवाल ने सभी से योग को केवल कार्यक्रमों तक सीमित न रखकर इसे घर-घर और जन-जन की दिनचर्या बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को स्वस्थ, निरोगी और नशामुक्त बनाने के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग की भागीदारी आवश्यक है और इस दिशा में योग आयोग निरंतर कार्य करता रहेगा।

मोबाइल का उपयोग सही दिशा में हो

छात्रों को संबोधित करते हुए संजय अग्रवाल ने वर्तमान समय में मोबाइल के बढ़ते उपयोग पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि मोबाइल और तकनीक स्वयं गलत नहीं हैं, लेकिन उनका उपयोग किस दिशा में किया जा रहा है, यह महत्वपूर्ण है। आज लोग कई बार वस्तु के आकर्षण पर अधिक ध्यान देते हैं, जबकि उसकी उपयोगिता और सही उद्देश्य को नजरअंदाज कर देते हैं। उन्होंने कहा कि मनुष्य का जन्म ईश्वर की चाह है, लेकिन मनुष्य से ईश्वरत्व की ओर बढ़ना स्वयं मनुष्य के हाथ में है। इसके लिए विचारों, व्यवहार और जीवनशैली में सकारात्मक बदलाव आवश्यक है।

पहले ऋषिपुत्र थे, आज शीशी पुत्र होते जा रहे हैं

अपने सहज और हास्यपूर्ण अंदाज में संजय अग्रवाल ने नशे की बढ़ती प्रवृत्ति पर गंभीर संदेश देते हुए कहा कि पहले यह भारत देश था, जहां लोग ऋषिपुत्र थे, आज लोग शीशी पुत्र होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नशे की जकड़न से समाज को मुक्त करना आज बड़ी आवश्यकता है। युवाओं को नशे से दूर रखने और स्वस्थ जीवनशैली की ओर प्रेरित करने में योग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि योग के माध्यम से शरीर के साथ-साथ मन को भी मजबूत बनाया जा सकता है और यही स्वस्थ एवं संस्कारवान समाज की नींव है।

ये प्रमुख लोग रहे उपस्थित

कार्यक्रम में प्रजामंडल संरक्षक भोला राम, प्रजामंडल अध्यक्ष दुलार राम नायक, गायत्री परिवार जिला प्रमुख शिव प्रसाद कोरेम, जिला पंचायत सदस्य कांकेर देवेंद्र टेकाम, ग्राम पटेल कुंवल सिंह दर्री, सरपंच सुनीता टेकाम, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उत्तर बस्तर विभाग कार्यवाह भावेराव साहू, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मंडल प्रमुख अरुण ताम्रकार, गायत्री परिवार सदस्य संपत राम सोनवानी, परगना देव प्रमुख नारद पटेल, जनपद सदस्य सरोज मरकाम, नारी जागरण प्रमुख विकासखंड भानुप्रतापपुर शांति पटेल, पूर्व जनपद सदस्य भानुप्रतापपुर पंचमी राम नायक एवं विश्व हिंदू परिषद के पूर्व प्रांतीय उपाध्यक्ष रामचरण कोरेम सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी, गायत्री परिवार के सदस्य एवं स्कूली छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

हर ग्राम में योग वाटिका और बस्तर में योग शिक्षकों की योजना

श्री अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ योग आयोग द्वारा योग को ग्रामीण स्तर तक पहुंचाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के प्रत्येक ग्राम में योग वाटिका विकसित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। साथ ही बस्तर क्षेत्र में 1,8 00 योग शिक्षकों की नियुक्ति की योजना पर भी कार्य किया जा रहा है, जिससे दूरस्थ अंचलों में भी लोगों को नियमित योग प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने और लोगों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के उद्देश्य से वेलनेस सेंटर विकसित किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना तथा बीमारियों से बचाव के लिए योग, प्राकृतिक एवं समग्र स्वास्थ्य पद्धतियों को बढ़ावा देना है।

बिहान से ग्रामीण महिलाओं को मिलेगा सिलाई प्रशिक्षण के जरिए स्वरोजगार का अवसर

श्रीकंचनपथ न्यूज

कोण्डागांव। कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना के निर्देशानुसार एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कोण्डागांव के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ''बिहान'' के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निरंतर आजीविका गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है।

इसी क्रम में जिला मिशन प्रबंधन इकाई, जिला पंचायत कोण्डागांव के सहयोग से विकासखण्ड कोण्डागांव के गरिमा महिला संगठन, दहिकोंगा क्लस्टर अंतर्गत ग्राम पंचायत जोबा स्थित पुलिस कैम्प में महिलाओं के लिए सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 31 अगस्त 2026 से प्रारंभ होकर एक माह तक संचालित किया जाएगा। प्रशिक्षण के लिए ग्रामीण क्षेत्र की 30 महिला स्व-सहायता समूह सदस्यों का चयन किया गया है। प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं को सूट, ब्लाउज, साड़ी सेट सहित विभिन्न प्रकार के वस्त्रों की सिलाई एवं संबंधित कार्यों का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य महिला स्व-सहायता समूह की सदस्यों को नई आजीविका गतिविधि से जोड़कर उन्हें स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना तथा उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना है।

तालाब बना आत्मनिर्भरता का आधार, वैज्ञानिक मत्स्य पालन से कामिनी की आय में हुआ इजाफा

श्रीकंचनपथ न्यूज

एमसीबी। मेहनत, सही तकनीक और विभागीय मार्गदर्शन का साथ मिले तो सीमित संसाधनों से भी बेहतर आमदनी का रास्ता तैयार किया जा सकता है। इसकी प्रेरक मिसाल हैं खोंगापानी, विकासखंड मनेन्द्रगढ़ की मत्स्य कृषक कामिनी रोहतिया, जिन्होंने वर्ष 2022 में मत्स्य विभाग के सहयोग से अपने लगभग 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के तालाब में वैज्ञानिक तरीके से मत्स्य पालन शुरू किया।

आज यही तालाब उनके लिए आय का महत्वपूर्ण साधन बन गया है और वे प्रतिवर्ष लगभग 2 लाख रुपये का लाभ प्राप्त कर रही हैं। मत्स्य पालन शुरू करने से पहले कामिनी मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर थीं। कृषि कार्य में मेहनत अधिक होने के बावजूद अपेक्षाकृत कम आय प्राप्त होती थी। वर्ष 2022 में मत्स्य विभाग की नवीन तालाब निर्माण योजना के अंतर्गत उन्हें लगभग 1 हेक्टेयर तालाब निर्माण का लाभ मिला। इसके बाद उन्होंने तालाब का बेहतर उपयोग करते हुए मत्स्य पालन को अपनी आजीविका का साधन बनाया। विभाग द्वारा उन्हें मत्स्य पालन की वैज्ञानिक तकनीक, तालाब प्रबंधन और मछलियों की देखभाल के संबंध में आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन दिया गया। विभागीय मार्गदर्शन के अनुसार उन्होंने तालाब में भारतीय प्रमुख कार्प प्रजाति की मछलियों का पालन शुरू किया। तालाब में लगभग 5 हजार फिंगरलिंग्स का स्टॉकिंग किया गया। कामिनी तालाब में मछलियों के उचित प्रबंधन, पानी की गुणवत्ता की नियमित निगरानी और समय-समय पर आवश्यक देखभाल पर विशेष ध्यान देती हैं। मत्स्य विभाग से प्राप्त प्रशिक्षण और तकनीकी सलाह के अनुसार वे तालाब प्रबंधन करती हैं। मछलियों में होने वाली संभावित बीमारियों की पहचान एवं रोकथाम के संबंध में भी उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। नियमित देखभाल और वैज्ञानिक पद्धति अपनाने का परिणाम उनकी आय में स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। वर्तमान में लगभग 1 हेक्टेयर तालाब से मत्स्य पालन के माध्यम से उन्हें करीब 2 लाख रुपये का वार्षिक लाभ प्राप्त हो रहा है।

बस्तर की 'ज्ञानगुड़ी' से निकले चार हीरे, पहले ही राउंड में एमबीबीएस सीट हासिल कर रचा गौरव

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ के दूरस्थ और आदिवासी अंचलों में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। आवश्यकता है तो केवल उन्हें सही दिशा, गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन और अवसर उपलब्ध कराने की। बस्तर जिला प्रशासन द्वारा इसी सोच के साथ संचालित निःशुल्क 'ज्ञानगुड़ी' कोचिंग संस्थान प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव की एक प्रेरक मिसाल बनकर उभर रहा है। संस्थान के चार होनहार विद्यार्थियों ने नीट की काउंसलिंग के पहले ही राउंड में शासकीय मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की सीट हासिल कर बस्तर का नाम रोशन किया है।

ज्ञानगुड़ी के विद्यार्थियों की यह सफलता इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उपलब्धि

उन युवाओं ने हासिल की है, जो बस्तर के दूरस्थ अंचलों से आते हैं और जिन्हें बेहतर उच्च शिक्षा के लिए महानगरों जैसी सुविधाएं सहज रूप से उपलब्ध नहीं थीं। जिला प्रशासन की पहल, शिक्षकों के समर्पित प्रयास और विद्यार्थियों की कठिन मेहनत ने इन परिस्थितियों को अवसर में बदल दिया।

चार विद्यार्थियों को मिली एमबीबीएस में प्रवेश की सफलता के तहत समीर मरकाम और गीतेश्वरी सलाम का चयन शासकीय मेडिकल कॉलेज, डिमरापाल जगदलपुर, कुमारी कृष्णा सेन का कांकेर मेडिकल कॉलेज तथा खुशबू बिस्वास का पं. जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर में हुआ है। पहले ही राउंड में शासकीय मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश मिलना विद्यार्थियों की उत्कृष्ट तैयारी और ज्ञानगुड़ी की प्रभावी शैक्षणिक व्यवस्था का प्रमाण है। कलेक्ट्रेट पहुंचकर बस्तर कलेक्टर आकाश छिकारा से सौजन्य मुलाकात की। विद्यार्थियों ने अपनी सफलता का श्रेय जिला प्रशासन के निरंतर सहयोग और कलेक्टर के मार्गदर्शन को दिया। कलेक्टर छिकारा ने विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनकी उच्च शिक्षा में डिजिटल अध्ययन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सभी सफल विद्यार्थियों को टैबलेट भेंट किए। उन्होंने विद्यार्थियों, उनके शिक्षकों और अभिभावकों की मेहनत की सराहना करते हुए कहा कि यह उपलब्धि केवल विद्यार्थियों की व्यक्तिगत सफलता नहीं, बल्कि बस्तर की नई पीढ़ी की क्षमता और संकल्प का प्रमाण है।

90 में से 50 विद्यार्थियों ने नीट में पाई सफलता

ज्ञानगुड़ी की उपलब्धि केवल चार एमबीबीएस चयन तक सीमित नहीं है। संस्थान में अध्ययनरत 90 विद्यार्थियों में से 50 विद्यार्थियों ने नीट परीक्षा उत्तीर्ण की है। इनमें से चार विद्यार्थियों ने काउंसलिंग के पहले ही चरण में सीधे एमबीबीएस की सीट हासिल की है। यह परिणाम बताता है कि यदि ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों को समय पर गुणवत्तापूर्ण कोचिंग, अध्ययन सामग्री और निरंतर मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाए, तो वे राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी किसी से पीछे नहीं हैं।

दर्री जोन में 07 नवनिर्मित सामुदायिक भवनों का हुआ लोकार्पण

उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन और महापौर संजूदेवी राजपूत ने किया जनसेवा में समर्पित

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। नगर पालिक निगम कोरबा के दर्री जोन अंतर्गत 07 नवनिर्मित सामुदायिक भवनों का लोकार्पण आज एक ही दिन पृथक-पृथक वार्डों में किया गया। प्रदेश के उद्योग, वाणिज्य, श्रम, आबकारी व सार्वजनिक उपक्रम मंत्री लखनलाल देवांगन के मुख्य आतिथ्य एवं महापौर संजू देवी राजपूत की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रमों के दौरान इन सभी सामुदायिक भवनों को जनता की सेवा में समर्पित किया गया।

कुल 90 लाख की लागत से बने हैं 7 भवन: नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा दर्री जोन में इन भवनों का निर्माण कराया गया है:- वार्ड क्र. 55 सलिहाभांठा' में 10 लाख रुपये की लागत से सामुदायिक भवन, वार्ड क्र. 55 नागिनभांठा बस्ती' में उप स्वास्थ्य केंद्र के समीप पटेल समाज हेतु 10 लाख की लागत से भवन, वार्ड क्र. 54 जमनीपाली हाउसिंग बोर्ड कालोनी' में 10 लाख की लागत से भवन, वार्ड क्र. 54 गोपालपुर' में माता चौरा के पास 10 लाख की लागत से अहातायुक्त सामुदायिक भवन, वार्ड क्र. 58 सरदार वल्लभभाई पटेल नगर साडा' में शिव मंदिर के समीप 15 लाख की लागत से भवन, वार्ड क्र. 59 दर्रीखार क्र. 01' में कन्या शाला के समीप 25 लाख की लागत से भवन, वार्ड क्र. 60 प्रगतिनगर लेबर कालोनी दर्री' में 10 लाख की लागत से उड़िया समाज के लिए सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया गया।

इस अवसर पर समाज के लोगों ने सामुदायिक भवनों की सौगात के लिए उद्योग मंत्री और महापौर के प्रति आभार व्यक्त किया।

बिना भेदभाव के सभी 67 वार्डों में विकास कार्य: महापौर

महापौर संजू देवी राजपूत ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव तथा उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन के मार्गदर्शन से नगर पालिक निगम कोरबा के सभी 67 वार्डों में बिना किसी भेदभाव के व्यापक रूप से विकास कार्य कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रदेश में 26 लाख आवासगृहों की स्वीकृति प्रदान की गई है। लोकार्पण कार्यक्रमों के दौरान सभापति नूतन सिंह ठाकुर, वरिष्ठ पार्षद नरेंद्र देवांगन, मेयर इन काउंसिल सदस्य अजय कुमार चंद्रा, सरोज शांडिल्य, फिरतराम साहू, पार्षदगण, एल्डरमेन ईश्वर साहू, मनोज अग्रवाल, मंडल अध्यक्ष मनोज लहरे, नरेंद्र पाटनवार सहित जोन कमिश्नर लीलाधर पटेल और बड़ी संख्या में वार्डवासी उपस्थित थे।

आमजन को अधिकाधिक सुविधाएं देना हमारा प्रथम लक्ष्य: मंत्री देवांगन

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि जनताजनार्दन को अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराना और उनकी विकास संबंधी समस्याओं का त्वरित समाधान करना मेरा प्रथम लक्ष्य है। इसी लक्ष्य को सामने रखकर निगम क्षेत्र में लगातार विकास कार्य कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय तथा उप मुख्यमंत्री व नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के मार्गदर्शन से विगत ढाई वर्षों के दौरान निगम क्षेत्र में 1100 करोड़ रुपये के विकास कार्य स्वीकृत हो चुके हैं, जिनमें से कई पूर्ण हो चुके हैं, कुछ प्रगति पर हैं और शेष निविदा प्रक्रिया में हैं।

जनदर्शन में दिव्यांग गौतम को मिली मोटराइज्ड ट्राई साइकिल

रायपुर। शासन की कल्याणकारी योजनाएं जरूरतमंदों के जीवन में सुविधा के साथ आत्मनिर्भरता की नई राह भी तैयार कर रही हैं। सूरजपुर के संजयनगर, अजबनगर निवासी बचपन से दिव्यांग श्री गौतम सिल को मोटराइज्ड ट्राई साइकिल मिलने से अब उनके दैनिक जीवन में आवागमन आसान होगा। साथ ही वे रोजगार के छोटे अवसरों से जुड़कर अपनी आजीविका को बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। दैनिक आवागमन में हो रही परेशानी को लेकर गौतम ने कलेक्टर रेना जमील से मुलाकात कर अपनी समस्या बताई थी। उनकी आवश्यकता को देखते हुए कलेक्टर ने समाज कल्याण विभाग को शासन की योजना के तहत आवश्यक कार्यवाही कर लाभान्वित करने के निर्देश दिए।

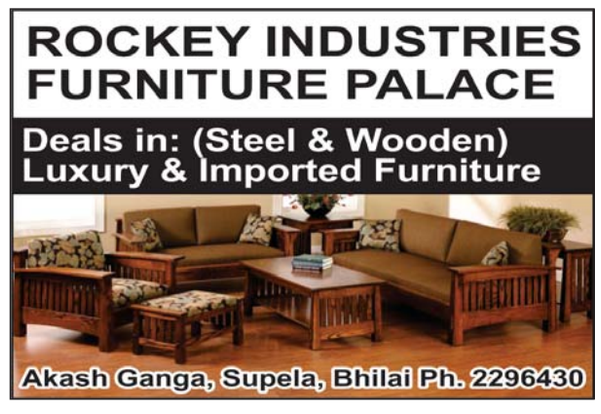

खास खबर

पूर्व डीईओ सुभाष गंजीर को 4 साल सश्रम कैद की सजा, दस हजार का अर्थ दंड

रायपुर। पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी सुभाष गंजीर को दंतेवाड़ा विशेष प्रधान सत्र न्यायाधीश की अदालत ने चार साल सश्रम क़ैद की सज़ा सुनाई है। वर्ष 2017 में एंटी करप्शन ब्यूरो ने तत्कालीन दंतेवाड़ा जिला शिक्षा अधिकारी गंजीर के ठिकानों पर दबिश देकर भ्रष्टाचार व आय से ज़्यादा संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किया था। विशेष सत्र न्यायाधीश ने ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1) और 13(2) के तहत दोष सिद्ध पाते हुए अभियुक्त गंजीर को चार साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10,000 रुपये का अर्थ दंड भी लगाया। मामले में सरकारी वकील ममता शर्मा ने अभियोजन अधिकारी के रूप में पैरवी की।

कवर्धा व लोहारा पुलिस ने 10.8 लीटर अवैध शराब जब्त की

कवर्धा। जिले में अवैध शराब के संग्रहण, परिवहन एवं बिक्री पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र कुमार यादव के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित पटेल के मार्गदर्शन तथा उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय आशीष शुक्ला के दिशा-निर्देश में कबीरधाम पुलिस द्वारा लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना सिटी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक लालजी सिन्हा के नेतृत्व में थाना कवर्धा पुलिस द्वारा ग्राम घोठिया में कार्रवाई करते हुए आरोपी सुखचैन पिता नैनदास चंदेल, उम्र 65 वर्ष, निवासी घोठिया, थाना सिटी कोतवाली कवर्धा को अवैध शराब का परिवहन करते पकड़ा गया। आरोपी के कब्जे से 5040/ मिलीलीटर शराब, जिसकी कीमत 3300/ रुपये है, गवाहों के समक्ष बरामद कर जब्त की गई। प्रकरण में थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 341/26, धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।

बस्तर में 28 लाख का 56 किलो गांजा जब्तःएक ओडिशा से स्कूटी से ला रहा था

जगदलपुर। बस्तर में गांजा तस्करी के खिलाफपुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। पिछले दो दिनों में पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में करीब 56 किलो गांजा जब्त कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की कुल कीमत करीब 28 लाख 7 हजार रुपए बताई गई है। पहले मामले में आरोपी ओडिशा से स्कूटी पर गांजा लेकर जगदलपुर आ रहा था, जिसे आड़ावाल रेलवे फाटक के पास पकड़ा गया। दूसरे मामले में आरोपी ने करीब 42 किलो गांजा अपने घर के आंगन की बाड़ी में जमीन के अंदर प्लास्टिक ड्रम में और घर के अंदर बोरी में छिपाकर रखा था। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

रायपुर में सड़क हादसे में युवक की मौत, 3 घायल

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। रायपुर-बलौदाबाजार मुख्य मार्ग पर मंगलवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया।

खरोरा थाना क्षेत्र के मंगोली चौक के पास ट्रक और क्रेटा कार की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में क्रेटा सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग घायल हुए हैं। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मृतक का नाम शिवम साहू बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक क्रेटा कार में ओमप्रकाश साहू, संजय साहू, शिवम साहू और रामेश्वर केंवट सवार थे।

सभी भटगांव से रायपुर की ओर जा रहे थे। मंगलवार सुबह मंगोली चौक के पास उनकी कार की ट्रक से जोरदार भिड़ंत हो गई।

टक्कर इतनी तेज थी कि क्रेटा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में कार सवार चारों लोगों को चोटें आईं। शिवम साहू की हालत गंभीर बताई गई। बाद में उसकी मौत होने की सूचना मिली। हालांकि पुलिस ने शव और मौत की स्थिति की चिकित्सकीय पुष्टि की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

घायलों को अस्पताल भेजा

हादसे की सूचना मिलने के बाद खरोरा पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए श्रीकृष्णा अस्पताल, खरोरा भेजा।

पुलिस ने घटनास्थल पर यातायात व्यवस्था भी संभाली। फिलहाल मार्ग पर आवागमन सामान्य बताया जा रहा है।

ट्रक चालक मौके से फरार

दुर्घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर चालक की तलाश शुरू कर दी है। हादसा किस वजह से हुआ, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ प्रत्यक्षदर्शियों से भी जानकारी जुटा रही है। फरार चालक की पहचान कर उसके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।

अपराध और असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने रायपुर कमिश्नरेट पुलिस का ऑपरेशन विश्वास जारी

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। अपराध और असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने रायपुर कमिश्नरेट पुलिस का ऑपरेशन विश्वास जारी है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में 24 से 30 अगस्त तक उत्तर, पश्चिम और मध्य जोन में व्यापक अभियान चलाया गया।

इस दौरान पुलिस ने स्थायी वारंटियों की धरपकड़ के साथ अवैध शराब, मादक पदार्थ और हथियारों के खिलाफ कार्रवाई की। अलग-अलग मामलों में पुलिस ने करीब 17 लाख 30 हजार रुपए की सामग्री जब्त की है।

गांजा-नशीली गोलियां और हेरोइन जब्त

पुलिस ने तीनों जोन में कार्रवाई के दौरान 273 पव्वा देशी शराब, 60.339 किलोग्राम गांजा, 1,590 प्रतिबंधित नशीली टेबलेट और 10.59 ग्राम हेरोइन बरामद की। पश्चिम जोन की कार्रवाई में सबसे बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ मिले। यहां गांजा, नशीली टेबलेट और हेरोइन के साथ 3 मोबाइल और एक स्कॉर्पियो वाहन भी जब्त किया गया।

20 चाकू और धारदार हथियार बरामद

सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लेकर घूमने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। आर्म्स एक्ट के तहत 20 प्रकरण दर्ज कर 20 आरोपियों पर कार्रवाई की गई। इनके कब्जे से 20 चाकू और धारदार हथियार बरामद हुए। उत्तर जोन में 2, पश्चिम में 12 और मध्य जोन में 6 हथियार जब्त किए गए।

सप्ताह तक चले अभियान में 82 वारंटी गिरफ्तार

एक सप्ताह तक चले अभियान में पुलिस ने स्थायी वारंट के 82 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आबकारी एक्ट के तहत 167 मामले दर्ज कर 167 आरोपियों पर कार्रवाई की गई। इसके अलावा धारा 170 बीएनएस के तहत 203 और धारा

गुंडा बदमाशों की चेकिंग

पुलिस ने आदतन अपराधियों, गुंडा बदमाशों और निगरानी बदमाशों की भी चेकिंग की।

उत्तर जोन में 62 गुंडा बदमाश और 32 निगरानी बदमाशों की जांच की गई। पुलिस के मुताबिक अपराधियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।

दंतेवाड़ा के तत्कालीन डीईओ को 4 साल की जेल

श्रीकंचनपथ समाचार

दंतेवाड़ा। आय से अधिक संपत्ति मामले में सुभाष गंजीर दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई सजाछत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के तत्कालीन डीईओ सुभाष गंजीर को आय से अधिक संपत्ति के मामले में विशेष अदालत ने 4 साल की जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन्हें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषी ठहराया है। मामले की शिकायत के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो और आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा ने सुभाष गंजीर से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की थी।

जांच के दौरान 8.71 लाख कैश, करीब 500 ग्राम सोने के आभूषण और संपत्तियों से जुड़े कई दस्तावेज बरामद किए गए थे। जांच एजेंसी को करीब 40 संपत्तियों और तीन मकानों से जुड़े दस्तावेज भी मिले थे। जांच में उनकी ज्ञात आय की तुलना में अधिक संपत्ति होने का मामला सामने आया। इसके बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई थी। जांच में करीब 40 संपत्तियों और 3 मकानों से जुड़े कागजात भी मिले थे।जानिए कब हुई थी कार्रवाईजांच के बाद ,ष्टक्र ने सुभाष गंजीर को 26 मई 2018 को गिरफ्तार किया था। उन्हें 5 जुलाई 2018 को जमानत मिल गई थी। मामले में 21 जून 2018 को चार्जशीट पेश की गई थी। इसके बाद 23 जुलाई 2018 को कोर्ट ने आरोप तय किए थे। कोर्ट रिकॉर्ड के अनुसार, उन पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(ई) और 13(2) के तहत मामला चलाया गया।

आय से 88.30% ज्यादा संपत्ति मिली

कोर्ट के फैसले के अनुसार, सुभाष गंजीर के पास उनकी आय से 88.30% ज्यादा संपत्ति मिली थी। कोर्ट ने मामले में पेश किए गए सबूत और गवाहों के बयान के आधार पर उन्हें दोषी माना।

ऑपरेशन आघातः जशपुर में 60 किलो गांजा के साथ अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार

श्रीकंचनपथ समाचार

जशपुर। नशे के खिलाफ जशपुर पुलिस का ऑपरेशन आघात लगातार जारी है। इसी अभियान के तहत थाना बागबहार क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 60 किलो अवैध गांजा के साथ एक अंतर्राज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से तस्करी में इस्तेमाल की जा रही वैन्यू कार भी जब्त की गई है। जब्त गांजे और वाहन की कुल कीमत करीब 40 लाख रुपये आंकी गई है।

पुलिस के अनुसार, 31 अगस्त की सुबह करीब 4 से 5 बजे के बीच जशपुर पुलिस की टेक्निकल टीम और विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि उड़ीसा की ओर से एक वैन्यू कार क्रमांक क्र-91- 6302 में भारी मात्रा में गांजा परिवहन किया जा रहा है। सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अवगत कराया गया। डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देशन में थाना बागबहार पुलिस ने तत्काल संभावित मार्गों पर नाकाबंदी और घेराबंदी की। इसी दौरान गांधी चौक बागबहार के पास संदिग्ध वैन्यू कार पहुंची, जिसे पुलिस टीम ने घेराबंदी कर रोक लिया।

वाहन चालक से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम विकास चौधरी (27 वर्ष) निवासी समस्तीपुर, बिहार, वर्तमान निवासी गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश बताया। गवाहों की मौजूदगी में पुलिस ने वाहन की तलाशी ली। कार की डिक्की में प्लास्टिक टेप से लिपटे 60 पैकेट मिले। जांच करने पर पैकेटों में कुल करीब 60 किलो अवैध गांजा बरामद हुआ।

पुलिस ने गांजा और तस्करी में प्रयुक्त वैन्यू कार को विधिवत जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

दर्दनाक हादसाः भारी वाहन ने तीन गौवंशों को कुचला

श्रीकंचनपथ समाचार

कोरबा। कटघोरा क्षेत्र में तेज रफ्तार भारी वाहन की चपेट में आने से तीन गौवंशों की मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल मवेशी घंटों सड़क किनारे तड़पते रहे। गौसेवकों ने प्रशासन, एनएचएआई और ग्राम पंचायत की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए घायल पशु-पक्षियों के लिए एम्बुलेंस और चिकित्सालय की मांग की है।

भटकते रहे लोग, नहीं मिली त्वरित व्यवस्था

ग्रामीणों और गौसेवकों के अनुसार, हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने घायल मवेशियों को बचाने का प्रयास किया, लेकिन शासन-प्रशासन, नेशनल हाईवे अथॉरिटी और ग्राम पंचायत स्तर से अपेक्षित त्वरित व्यवस्था नहीं हो सकी। बताया जा रहा है कि पंचायत प्रतिनिधियों से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन सरपंच और सचिव ने फोन तक रिसीव नहीं किया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की ओर से कथित तौर पर वाहन उपलब्ध नहीं होने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया गया।

जिम्मेदारी पर सवाल

यह स्थिति कई गंभीर सवाल खड़े करती है। क्या नेशनल हाईवे पर दुर्घटना के बाद घायल या मृत पशुओं को हटाने की कोई तत्काल व्यवस्था नहीं है? क्या सड़क हादसे के बाद घंटों तक घायल जीव को तड़पते रहने देना व्यवस्था की विफलता नहीं है? क्या ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी केवल कागजों तक सीमित रह गई है?

सड़क पर मवेशी, लगातार हो रहे हादसे

स्थानीय लोगों का कहना है कि देर रात नेशनल हाईवे पर भारी वाहन बेलगाम गति से दौड़ते हैं और रफ्तार पर अंकुश लगाने वाला कोई नहीं है। सड़क पर घूम रहे मवेशियों को हटाने के लिए भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसके कारण लगातार हादसे हो रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही दर्री मुख्य मार्ग पर 11 मवेशी भारी वाहन की चपेट में आ गए थे, जिसमें कई की मौत हो गई थी।उस घटना के बाद गौसेवकों ने चक्काजाम कर विरोध जताया था, लेकिन व्यवस्था नहीं सुधरी।

एम्बुलेंस और चिकित्सालय की मांग

गौसेवकों ने शासन-प्रशासन, एनएचएआई और ग्राम पंचायत से मांग की है कि इस मामले की गंभीरता से जांच की जाए और भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने, इसके लिए तत्काल आपातकालीन व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सवाल सिर्फ गौवंश का नहीं है, सवाल सड़क सुरक्षा, जिम्मेदारी और संवेदनशीलता का है। गौसेवकों ने घायल पशु-पक्षियों के लिए एम्बुलेंस और चिकित्सालय की व्यवस्था की मांग की है।

व्यवस्था ने मुंह मोड़ा तो ग्रामीणों ने संभाला मोर्चा

जब जिम्मेदार विभाग और अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटते नजर आए, तब एक बार फिर स्थानीय ग्रामीणों और गौसेवकों को ही आगे आना पड़ा। ग्रामीणों का कहना है कि यह घटना केवल एक सड़क हादसा नहीं है।

रायगढ़ में पुरानी रंजिश को लेकर चाकूबाजी, युवक घायलः 6-7 लोगों ने मिलकर चाकू-डंडे से किया हमला

श्रीकंचनपथ समाचार

रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में देर रात गुटखा खाने जा रहे एक युवक का कुछ युवकों ने रास्ता रोक लिया। पुरानी रंजिश को लेकर आरोपियों ने उसके साथ गाली-गलौज करते हुए चाकू और डंडे से मारपीट की। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वारदात के बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए। घायल युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक, बापूनगर निवासी सुषमा दीप ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि वह जिला अस्पताल में प्राइवेट नौकरी करती हैं। उनका 22 साल का बेटा पालेश्वर दीप रात करीब डेढ़ बजे गुटखा खाने के लिए घर से निकला था। इसी दौरान हनुमान मंदिर के आगे बापूनगर के पास पुरानी रंजिश को लेकर कृष्णा डोंगरे और उसके साथियों ने उसका रास्ता रोक लिया। फिर आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए डंडे और चाकू से उसके साथ जमकर मारपीट की। जान से मारने की धमकी देकर सभी आरोपी मौके से फरार हो गए।

घटना की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और पालेश्वर को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। इसके बाद कोतवाली थाने पहुंचकर मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी कृष्णा डोंगरे और उसके करीब 6-7 साथियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

चाकू और डंडे से किए गए हमले में पालेश्वर के सिर, पेट और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं। आसपास के लोगों ने घटना की जानकारी उसके परिजनों को दी। परिजनों के मुताबिक, करीब एक साल पहले मोहल्ले के कुछ युवकों से पालेश्वर का किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद उस पर दो बार हमला करने का प्रयास किया जा चुका था। इस बार आरोपियों ने उसे अकेला पाकर मारपीट की। फिलहाल युवक का जिला अस्पताल में इलाज जारी है।

भालुओं के झुंड ने राहगीर पर किया हमला

कांकेर। कांकेर जिले के चारामा ब्लॉक के हल्बा चौकी क्षेत्र के बड़ाटोला गांव में सोमवार देर रात भालुओं के झुंड ने एक राहगीर पर हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए कांकेर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार, जेपरा निवासी मिथलेश गंगबेर सोमवार रात करीब 12 बजे बड़ाटोला क्षेत्र से गुजर रहे थे। इसी दौरान रास्ते में उनका सामना भालुओं के झुंड से हो गया। भालुओं ने अचानक मिथलेश पर हमला कर दिया, जिससे उनके शरीर पर गंभीर चोटें आईं। हमले के दौरान मिथलेश की चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों को आता देख भालू जंगल की ओर भाग गए।

NAME CHANGE

It is informed to the general public that I, MRITUNJAY KUMAR SINGH S/O MAHARAJ SINGH Resident of 33/e, Prem Nagar, 18 Nomber Road, Post Supela, Bhilai, Dist Durg (C. G.) Pin Code 490023 have changed my old name MRITUNJAY KUMAR SINGH S/O MAHARAJ SINGH So in future I should be recognized by my new name that is MRITUNJAY SINGH S/O MAHARAJ SINGH in all Government and other documents.

MRITUNJAY SINGH
Address - 33/e
Prem Nagar, 18 Nomber
Road, Post Supela, Bhilai
Dist Durg (C.G.) Pin 490023

OFFICE OF THE SUPERINTENDING ENGINEER
PUBLIC WORKS DEPARTMENT, E/M CIRCLE, RAIPUR (C.G.)
e-Procurement Tender Notice

Online tenders are invited on behalf of Governor of Chhattisgarh from contractors, C.G. P.W in new Registration system (unified Registration system) for the following work :-

NIT No.	Name of work	Probable amount of contract
71/SE E/M/2026-27 (I Call) System Tender No Registered contractor class in "C" & above For Form A (Percentage rate)	PROVIDING ELECTRIFICATION & ROAD LIGHTING WORK AT NANDINI ROAD TO AWANTIBAI CHOWK CANNAL ROAD 4.8 KM DISST.- DURG	Rs 152.99 Lacs
72/SE E/M/2026-27 (I Call) System Tender No Registered contractor class in "C" & above For Form A (Percentage rate)	Providing & Installation of Street Road Lighting,High mast & LED strip RGB lighting E/F Work Rajnandgaon-Gundardehi-Dhamtari Nagri-Sihawa-Borai (SH-23) from Sihawa Chowk to Naharnaka (Four Lane) Road (phase 2-Danitola road junction TO Naharnaka), , Distt. - Dhamtari (C.G.)	Rs 175.43 Lacs
75/SE E/M/2026-27 (I Call) System Tender No Registered contractor class in "D" & above For Form A (Percentage rate)	SUPPLYING & FIXING OF L.E.D. STREET LIGHTING, AT NAYAKTAND TO KHARORA GAURAV PATH (LENGTH- 2.5 K.M.) DISTT.- RAIPUR (C.G.)	Rs 38.62 Lacs

Date of bid submission 17-09-2026 The tender documents can be downloaded from the web-portal http://eproc.cgstate.gov.in. Only those contractors/bidders, interested in bidding shall pay the tender document cost online.

Superintending Engineer
P. W. D. (E & M) Circle
Raipur (C. G.)

G-262703033/10

Ashok
JEWELLERY
Gifts • Toys • Cosmetics
Perfumes • Silv Jewellery
Beside Parakh Jewellers,
Akash Ganga,
Supela, Bhilai
Hello: 0788-4052727
Mukesh Jain 9009959111
Rishabh Jain 8103831329

Shop-47, 'A' Market, Sec-6, Bhilai Nagar, Distt., Durg (C.G.)

भिलाई मसाला उद्योग
शुद्ध कुटे हुए मसाले,पापड़,
अचार, बड़ी, जड़ी-बूटी, नचकी
का सामान इत्यादि
128, ए- मार्केट, सेक्टर-6, भिलाई,
फोन. 2284508, मो. 9826137766

खास खबर

ढलानों पर बनेगी जल-संरक्षण की राह, संवरेंगे खेत और गांव

रायगढ़। वर्षा जल के बेहतर प्रबंधन, मिट्टी के कटाव को रोकने और ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में रायगढ़ जिले में स्टैगर्ड कंटूर ट्रेंच एवं कंटूर ट्रेंच निर्माण के कार्य स्वीकृत किए गए हैं। ढलान वाले क्षेत्रों में किए जा रहे ये कार्य वर्षा जल के तेज बहाव को नियंत्रित कर उसे भूमि में समाहित करने में सहायक होंगे, जिससे खेतों की नमी और भूमि की उत्पादकता को बनाए रखने में मदद मिलेगी। जिले में कुल 16 हजार 873 ट्रेंच निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो लगभग 38.27 एकड़ क्षेत्र में निर्मित किए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत रायगढ़, खरसिया और तमनार विकासखंड की विभिन्न ग्राम पंचायतों में कुल 28 कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इनमें रायगढ़ विकासखंड में 6, खरसिया में 16 तथा तमनार विकासखंड में 6 कार्य शामिल हैं।

सुकमा के सुदूर वनांचल टेटरई में लगा बीएसएनएल टावर

सुकमा। सुकमा के सुदूर वनांचल अब विकास की नई सुबह देख रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन जिला प्रशासन की सक्रियता और निरंतर निगरानी के चलते जिला मुख्यालय से करीब 190 किलोमीटर दूर कोंटा विकासखंड के टेटरई जैसे अति-संवेदनशील व अंदरूनी गांवों में नया मोबाइल टॉवर स्थापित कर नेटवर्क बहाल कर दिया गया है। कलेक्टर अमित कुमार के अनुसार, बीएसएनएल की '4जी सैचुरेशन परियोजना' के तहत जिले के दुर्गम क्षेत्रों को निर्बाध कॉलिंग और इंटरनेट कनेक्टिविटी से लैस किया जा रहा है। सुकमा के इन वनांचलों में गूंजती मोबाइल की यह घंटी केवल संचार का साधन नहीं, बल्कि बस्तर के सुरक्षित, सशक्त और विकसित भविष्य की बुलंद आवाज बन चुकी है।

पाताकुटरू में मोबाइल टॉवर से बदली संचार की तस्वीर

बीजापुर। जिले के दूरस्थ वनांचल क्षेत्र स्थित पाताकुटरू गांव में नए मोबाइल टॉवर का निर्माण एवं संचालन शुरू होने से ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है। ग्राम पंचायत मंगापेठा के अंतर्गत आने वाले पिताकुटरू में लंबे समय से मोबाइल नेटवर्क की समस्या बनी हुई थी। अब टॉवर के शुरू होने से ग्रामीणों को मोबाइल नेटवर्क एवं इंटरनेट की बेहतर सुविधा मिलने लगी है। घने जंगलों और दूरस्थ भौगोलिक क्षेत्र में स्थित होने के कारण पाताकुटरू के ग्रामीणों के लिए संचार सुविधा हमेशा एक बड़ी चुनौती रही है। मोबाइल नेटवर्क की कमी के चलते जरूरी फोन कॉल करने के लिए भी लोगों को कई बार ऊंचे स्थानों या नेटवर्क उपलब्ध होने वाले दूसरे क्षेत्रों तक जाना पड़ता था। ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग भी ग्रामीणों के लिए मुश्किल था। अब ग्रामीणों को मोबाइल कॉल और इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध होगी। इसका सबसे अधिक लाभ गांव के विद्यार्थियों और युवाओं को मिलेगा। विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ाई और शैक्षणिक सामग्री का उपयोग कर सकेंगे।

आकस्मिक निरीक्षण में खुली स्कूलों की लापरवाही, डीईओ ने दिया वेतन रोकने का आदेश

मुंगेली। कलेक्टर अमृत विकास तोपनो के निर्देशानुसार जिले में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने और स्कूलों में शिक्षकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्कूलों का आकस्मिक निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में जिला शिक्षा अधिकारी एलपी डाहिरे ने प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला दुल्लापुर का आकस्मिक निरीक्षण किया, जहां निर्धारित स्टॉफ में से केवल दो शिक्षक उपस्थित पाए गए, जबकि शेष स्टॉफ अनुपस्थित मिला। डीईओ ने बताया कि अनुपस्थित कर्मचारियों को शोकॉज नोटिस जारी करते हुए एक दिवस का वेतन रोकने की कार्यवाही की गई है। इसी प्रकार हाई स्कूल झलियापुर के निरीक्षण के दौरान भी केवल एक शिक्षक उपस्थित पाया गया, जबकि शेष स्टॉफ अनुपस्थित मिला। मामले को गंभीरता से लेते हुए अनुपस्थित कर्मचारियों को शोकॉज नोटिस जारी करने तथा एक दिवस का वेतन रोकने की कार्यवाही की गई। निरीक्षण के दौरान दोनों विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन का संचालन भी नहीं होना पाया गया, जिस पर संबंधित जिम्मेदारों को आवश्यक कार्यवाही करने एवं व्यवस्था में तत्काल सुधार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

अब केवल खनिज उत्पादन तक सीमित नहीं रहेगा छत्तीसगढ़

खनिज से अंतिम उत्पाद तक बनेगी पूरी वैल्यू चेन : साय

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। छत्तीसगढ़ में उपलब्ध समृद्ध खनिज संपदा और क्रिटिकल मिनरल्स की व्यापक संभावनाएं प्रदेश को विकास के नए क्षितिज पर ले जाने की क्षमता रखती हैं। हमारा लक्ष्य केवल धरती से खनिज निकालना नहीं, बल्कि अन्वेषण से उत्खनन, प्रसंस्करण से मूल्य संवर्धन और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग से रिसाइक्लिंग तक पूरी मिनरल वैल्यू चेन छत्तीसगढ़ में विकसित करना है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर स्थित मेफेयर लेक रिजॉर्ट में भारत सरकार के खान मंत्रालय द्वारा आयोजित क्रिटिकल एवं स्ट्रेटेजिक मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी की आठवीं किश्त के रोड शो को संबोधित करते हुए यह बात कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे प्रदेश में निवेश बढ़ेगा, नए उद्योग स्थापित होंगे और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। क्रिटिकल एवं स्ट्रेटेजिक मिनरल्स आने वाले समय में देश की आर्थिक प्रगति, तकनीकी आत्मनिर्भरता और सामरिक सुरक्षा के प्रमुख आधार होंगे। आज के तेजी से बदलते वैश्विक और तकनीकी परिदृश्य में इन खनिजों का महत्व बहुत आगे बढ़ चुका है। रक्षा उद्योग से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग तक आधुनिक अर्थव्यवस्था के लगभग हर उभरते क्षेत्र के लिए इन खनिजों की विश्वसनीय उपलब्धता आवश्यक है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने ई-रेत संगवारी पोर्टल और टिन पोर्टल का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम (सीएमडीसी) द्वारा इंडियन ओवरसीज बैंक तथा पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के साथ महत्वपूर्ण एमओयू भी किए गए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से दुनिया की प्रमुख आर्थिक और तकनीकी शक्तियों में अपनी जगह बना रहा है। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के माध्यम से देश में क्रिटिकल मिनरल्स के अन्वेषण, प्रसंस्करण और इनसे जुड़े उन्नत उद्योगों के विकास को नई गति मिली है।

पहले यह लगभग 12 हजार करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 16 हजार करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। उन्होंने कहा कि खनिज संपदा से प्राप्त राजस्व का उपयोग प्रदेश के विकास और जनकल्याण में किया जा रहा है। जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) के माध्यम से खनन प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के साथ स्थानीय लोगों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने उद्योग जगत और निवेशकों से छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में भागीदार बनने का आह्वान करते हुए कहा कि आज पूरा देश छत्तीसगढ़ की ओर देख रहा है। प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है और तेजी से औद्योगिक एवं आर्थिक विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि यह रोड शो छत्तीसगढ़ में निवेश, तकनीकी सहयोग और नई साझेदारियों के लिए मजबूत आधार तैयार करेगा तथा प्रदेश को देश की क्रिटिकल मिनरल वैल्यू चेन के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।

नई अर्थव्यवस्था की आधारशिला हैं क्रिटिकल मिनरल्स

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का रक्षा उद्योग तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय रक्षा क्षमताओं और स्वदेशी तकनीक की प्रभावशीलता को दुनिया ने देखा। आधुनिक रक्षा उपकरणों के निर्माण में अनेक स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए एक मजबूत और आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग के लिए इनकी सुरक्षित और निरंतर आपूर्ति जरूरी है। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार एआई, सेमीकंडक्टर, बैटरी, क्लीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, डिजिटल प्रौद्योगिकी और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के लिए लिथियम, ग्रेफाइट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, वैनेडियम, निकेल और क्रोमियम जैसे खनिज अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। भविष्य की अर्थव्यवस्था में इनकी भूमिका लगातार बढ़ने वाली है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश के प्रमुख खनिज संपन्न राज्यों में है और अब क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में भी प्रदेश नई पहचान बनाने की ओर अग्रसर है। कटघोरा और बस्तर में लिथियम एवं दुर्लभ मृदा तत्व, बलरामपुर में ग्रेफाइट, वैनेडियम एवं गैलियम, बालोद में फास्फोराइट तथा महासमुंद में निकेल, क्रोमियम और ग्लाकोनाइट की संभावनाएं मौजूद हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि क्रिटिकल एवं स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की नीलामी की आठवीं किश्त में देश के 7 राज्यों के 20 खनिज ब्लॉक्स शामिल हैं, जिनमें छत्तीसगढ़ के 5 ब्लॉक्स हैं। मुख्यमंत्री ने निवेशकों से इन ब्लॉक्स की नीलामी में सक्रिय भागीदारी का आह्वान करते हुए कहा कि यह केवल खनिज ब्लॉक हासिल करने का अवसर नहीं है। यह अन्वेषण, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, नवाचार और नए उद्योगों के माध्यम से छत्तीसगढ़ तथा देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने का अवसर है। ये क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स विकसित भारत के निर्माण की महत्वपूर्ण धुरी बन सकते हैं।

पूरी मिनरल वैल्यू चेन छत्तीसगढ़ में विकसित करने पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की सोच खनिज उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं है। हमारा प्रयास है कि खनिज आधारित उद्योगों की पूरी वैल्यू चेन प्रदेश में विकसित हो। अन्वेषण और उत्खनन के बाद खनिज बाहर भेजने के बजाय उनका प्रसंस्करण, वैल्यू एडिशन और उनसे संबंधित एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रदेश में हो, ताकि प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम आर्थिक लाभ छत्तीसगढ़ और यहां के लोगों को मिले।

उन्होंने कहा कि नवा रायपुर में एआई आधारित डेटा सेंटर पार्क और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर तथा राजनांदगांव में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं। ऐसे आधुनिक उद्योगों में क्रिटिकल मिनरल्स की आवश्यकता होगी। खनिज संसाधनों की निकट उपलब्धता प्रदेश को इन उद्योगों के लिए स्वाभाविक प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त प्रदान करेगी।

नई औद्योगिक नीति और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से निवेश को प्रोत्साहन

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार नए जमाने के उद्योगों को आकर्षित करने के लिए निवेश अनुकूल वातावरण तैयार कर रही है। नई औद्योगिक नीति में अनेक प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम के माध्यम से कम एवं मध्यम जोखिम वाले उद्योगों के लिए आवश्यक औपचारिकताओं को सरल किया गया है। वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 से विभिन्न अनुमतियों और एनओसी की प्रक्रिया भी सुगम हुई है। उन्होंने कहा कि पूंजी निवेश सहायता, स्टांप शुल्क एवं विद्युत शुल्क में छूट, ब्याज अनुदान और रोजगार आधारित प्रोत्साहन सहित विभिन्न सुविधाएं निवेशकों को उपलब्ध कराई जा रही हैं। राज्य में खनिज संपदा, ऊर्जा, भूमि, कनेक्टिविटी और औद्योगिक अधोसंरचना की उपलब्धता क्रिटिकल मिनरल आधारित उद्योगों के लिए मजबूत इकोसिस्टम तैयार करती है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में दुनिया के सभी प्रमुख देश अपने रणनीतिक संसाधनों और उनकी सप्लाई चेन को सुरक्षित करने में जुटे हैं। ऐसे समय में भारत के लिए क्रिटिकल एवं स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की उपलब्धता में आत्मनिर्भर होना आर्थिक आवश्यकता के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य निर्माण के समय छत्तीसगढ़ का खनिज राजस्व लगभग 400 करोड़ रुपए था। ढाई वर्ष

निवेशकों को हर स्तर पर मिलेगा हैंडहोल्डिंग सपोर्ट : मुख्य सचिव विकास शील

मुख्य सचिव श्री विकास शील ने कहा कि राज्य सरकार खनिज क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के साथ पूरी वैल्यू चेन विकसित करने की दिशा में काम कर रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए 43 सेवाओं को रिस्क रेटेड अप्रोच के तहत अधिसूचित किया गया है। लो और मीडियम रिस्क गतिविधियों के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन तथा हाई रिस्क गतिविधियों के लिए आवश्यक अनुमति की व्यवस्था की जा रही है।

उन्होंने कहा कि औद्योगिक परियोजनाओं की समयबद्ध स्थापना के लिए रणनीतिक परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग, श्रम कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन और भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। खनन क्षेत्र में सर्वे, एनफोर्समेंट, परिवहन, रॉयल्टी भुगतान और नीलामी प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाया जा रहा है तथा भविष्य में ट्रांसपोर्ट सिस्टम को और अधिक तेज तथा पेपरलेस बनाने का लक्ष्य है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पर्यावरण, वन, भूमि अधिग्रहण एवं अन्य आवश्यक स्वीकृतियों में निवेशकों को सक्रिय हैंडहोल्डिंग सपोर्ट दे रही है। अब खनिज ब्लॉक्स की नीलामी लैंड शेड्यूलिंग के बाद की जा रही है, जिससे निवेशकों को भूमि, वन क्षेत्र एवं संबंधित प्रक्रियाओं की स्पष्ट जानकारी पहले ही उपलब्ध हो सके।

मुख्य सचिव ने निवेशकों से केवल खदानों में निवेश तक सीमित न रहते हुए पूरी मिनरल वैल्यू चेन और डाउनस्ट्रीम उद्योगों में निवेश करने का आग्रह किया। उन्होंने स्थानीय समुदायों की भागीदारी बढ़ाने वाले नए बिजनेस मॉडल विकसित करने पर भी जोर दिया।

देश में अब तक 56 क्रिटिकल एवं स्ट्रेटेजिक मिनरल ब्लॉक्स की सफल नीलामी

भारत सरकार के खान मंत्रालय के सचिव केशव चंद्र ने कहा कि भारत के वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने और स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों की ओर तेजी से आगे बढ़ने के साथ क्रिटिकल एवं स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। ये खनिज इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, नवीकरणीय ऊर्जा, बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, रक्षा, एयरोस्पेस और उर्वरक सहित अनेक उन्नत उद्योगों के लिए जरूरी हैं। केंद्र सरकार को क्रिटिकल एवं स्ट्रेटेजिक मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी का अधिकार मिलने के बाद अब तक 88 ब्लॉक्स की नीलामी प्रक्रिया शुरू की गई है, जिनमें 56 ब्लॉक्स की सफलतापूर्वक नीलामी हो चुकी है।

उन्होंने छत्तीसगढ़ की खनिज संभावनाओं की सराहना करते हुए कहा कि भारत के पहले लिथियम युक्त खनिज ब्लॉक की नीलामी छत्तीसगढ़ के कटघोरा लिथियम एवं रेयर अर्थ एलिमेंट ब्लॉक से हुई। आठवीं किश्त में 7 राज्यों के 20 खनिज ब्लॉक्स में से 5 छत्तीसगढ़ में हैं।

उन्होंने बताया कि नीलामी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, समयबद्ध और निवेशक अनुकूल बनाने के लिए माइलस्टोन आधारित अनुपालन, समयबद्ध स्वीकृतियों, यूनिफाइड माइनिंग पोर्टल और बीमा सिक्योरिटी बॉन्ड जैसे अनेक सुधार किए गए हैं। उन्होंने निवेशकों से इन अवसरों का लाभ उठाते हुए भारत के सुरक्षित और आत्मनिर्भर क्रिटिकल मिनरल इकोसिस्टम के निर्माण में भागीदार बनने का आग्रह किया।

वैज्ञानिक अन्वेषण और पारदर्शी व्यवस्था पर विशेष जोर : खनिज सचिव पी. दयानंद

खनिज विभाग के सचिव पी. दयानंद ने कहा कि राज्य सरकार खनिज संपदा के सतत उपयोग, वैज्ञानिक अन्वेषण, पारदर्शी नीलामी और निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने की दिशा में लगातार कदम उठा रही है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण सहित विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से वैज्ञानिक सर्वेक्षण, भू-आंकड़ों के संकलन और मैपिंग को मजबूत कर रही है। ऑनलाइन एवं पारदर्शी व्यवस्थाओं का विस्तार किया जा रहा है, ताकि संभावित खनिज क्षेत्रों को तेजी से उत्पादनशील खदानों में परिवर्तित किया जा सके। सरकार का लक्ष्य खनिज उत्खनन के साथ खनिज आधारित उद्योग, स्थानीय रोजगार, तकनीकी विकास और मूल्य संवर्धन को भी गति देना है।

सीएमडीसी के दो महत्वपूर्ण एमओयू, कौशल विकास और वित्तीय सहयोग को मिलेगी गति

कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम और इंडियन ओवरसीज बैंक के बीच एमओयू किया गया। इसके साथ ही कोरन्डम कटिंग एवं पॉलिशिंग के प्रशिक्षण के लिए सीएमडीसी और पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के बीच भी एमओयू हुआ। इन समझौतों से खनिज क्षेत्र में वित्तीय सहयोग, कौशल विकास, मूल्य संवर्धन और निवेश की संभावनाओं को नई गति मिलेगी।

इस अवसर पर माइनर मिनरल्स पर प्रकाशित पुस्तक का विमोचन किया गया तथा तीन लाइमस्टोन माइनिंग लीज ब्लॉक्स के लिए एनआईटी जारी करने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई गई। कार्यक्रम में केंद्रीय खान मंत्रालय के संयुक्त सचिव संदीप बसंत कदम सहित केंद्र एवं राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, खनिज क्षेत्र से जुड़े निवेशक, उद्योग प्रतिनिधि, विशेषज्ञ और विभिन्न स्टेकहोल्डर्स उपस्थित थे।

क्रिटिकल मिनरल्स में आत्मनिर्भरता देश की रणनीतिक आवश्यकता : केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे

केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि क्रिटिकल एवं स्ट्रेटेजिक मिनरल्स में आत्मनिर्भरता भारत की आर्थिक और रणनीतिक शक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। लंबे समय तक देश अनेक महत्वपूर्ण खनिजों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ इस दिशा में तेजी से काम हुआ है। उन्होंने कहा कि क्रिटिकल मिनरल्स का उपयोग वाहनों, इनवर्टर और ई-रिक्शा से लेकर जहाजों तथा आधुनिक रक्षा उपकरणों तक में होता है। उन्होंने निवेशकों, युवाओं और स्टार्टअप्स से इस क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य केवल खनिजों का दोहन नहीं, बल्कि सतत और जिम्मेदार खनन को बढ़ावा देना है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय समुदायों के हितों का विशेष ध्यान रखा जाए।

खनन के साथ सुनियोजित और टिकाऊ विकास भी जरूरी : केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू

केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि खनिज ब्लॉक्स की नीलामी की सफलता केवल उनके आवंटन से नहीं मापी जानी चाहिए। इसका वास्तविक प्रभाव अन्वेषण, निवेश, प्रोसेसिंग सुविधाओं की स्थापना, तकनीकी विकास, वैल्यू एडिशन और रोजगार सृजन के रूप में दिखाई देना चाहिए। खनन और औद्योगिक निवेश के साथ आवास, परिवहन, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी नागरिक सुविधाओं का सुनियोजित विकास भी जरूरी है। इसके लिए सरकार और उद्योग जगत के बीच मजबूत साझेदारी आवश्यक है।

ढाई साल में 40 एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट, 2800 किलोमीटर जियोलॉजिकल सर्वे

खनिज विभाग के संचालक एवं सीएमडीसी के प्रबंध संचालक रजत बंसल ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर प्रदेश में सतत खनन पद्धतियों के साथ खनिज संसाधनों के वैज्ञानिक अन्वेषण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष में प्रदेश को लगभग 16 हजार 700 करोड़ रुपए का खनिज राजस्व प्राप्त हुआ, जो निर्धारित लक्ष्य का करीब 98 प्रतिशत है। खनिज राजस्व में वर्ष-दर-वर्ष लगभग 14 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

उन्होंने बताया कि पिछले ढाई वर्षों में राज्य में 40 एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं और 2,800 किलोमीटर से अधिक जियोलॉजिकल सर्वे पूरा किया गया है। प्रदेश में अब तक 65 खनिज ब्लॉक्स की नीलामी की गई है, जिनसे लगभग 4 लाख करोड़ रुपए के संभावित राजस्व की उम्मीद है।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में लिथियम, ग्रेफाइट, वैनेडियम, गैलियम, गोल्ड, टंगस्टन, निकेल, क्रोमियम, कॉपर, लेड-जिंक और डायमंड सहित विभिन्न महत्वपूर्ण खनिजों की व्यापक संभावनाएं हैं। कटघोरा में लिथियम, बलरामपुर में ग्रेफाइट-वैनेडियम-गैलियम तथा बस्तर के टिन बेल्ट सहित विभिन्न क्षेत्रों में अन्वेषण एवं नीलामी की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। खनिज ऑनलाइन 2.0, डीएमएफ2.0 और ई-नीलामी जैसी डिजिटल व्यवस्थाओं के माध्यम से खनिज क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही मजबूत की गई है। खदानों और माइनर मिनरल्स की निगरानी के लिए ड्रोन सर्वे का भी उपयोग किया जा रहा है।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री साय ने ई-रेत संगवारी पोर्टल का शुभारंभ किया। इसके माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को रियायती दर पर रेत उपलब्ध कराने की व्यवस्था को अधिक सुगम और पारदर्शी बनाया जाएगा।

इसी प्रकार दंतेवाड़ा क्षेत्र में टिन से जुड़े आदिवासी समुदायों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से टिन पोर्टल शुरू किया गया है। इन डिजिटल पहलों से खनिज प्रशासन में तकनीक के उपयोग के साथ आम नागरिकों को सीधे लाभ पहुंचाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ा है।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक राजेश अग्रवाल द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि. छत्तीसगढ़ भवन, प्रेस काम्पलेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित कर, 204 आकाशगंगा सुपेला, भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.) से प्रकाशित। संपादक राजेश अग्रवाल shreekanchanpath2010@gmail.com, Mo - 9303289950